वर्ष 13 • अंक 14 • 16 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

मंगलवार 3 मार्च 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 13
जिंसों में सुधार मगर आशंका बरकरार

जेम्स क्विंसी पृष्ठ 2
कोका-कोला का तीसरा सबसे बड़ा बाजार होगा भारत

डॉलर रु. 72.70 ▲ 50 पैसे | यूरो रु. 80.70 ▲ 01.20 पैसे | सोना (10ग्राम) ₹42157 ▼ 197 रुपये | सेंसेक्स 38144.20 ▼ 153.30 | निफ्टी 11132.80 ▼ 69.00 | निफ्टी फ्यूचर्स 11123.70 ▼ 09.00 | ब्रेंट क्रूड 50.20 डॉलर ▲ 0.20 डॉलर

एक नज़र

फरवरी में नरम पड़ीं विनिर्माण गतिविधियां

दुनिया के कई देशों में कोरोनावायरस फैलने का असर फरवरी महीने के दौरान भारत में विनिर्माण गतिविधियों पर देखा गया। इस दौरान विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में कुछ नरमी देखी गई। सोमवार को जारी एक मासिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है। आईएचएस मार्किट इंडिया के विनिर्माण क्षेत्र के पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) फरवरी में 54.5 पर रहा। यह आंकड़ा जनवरी के 55.3 अंक के मुकाबले नीचे है। जनवरी में यह पिछले आठ साल में सबसे ऊंचा था। फरवरी में यह आंकड़ा 54.5 अंक पर रहा जो कि क्षेत्र में विस्तार जारी रहना बताता है। हालांकि यह विस्तार जनवरी के मुकाबले कुछ सुस्त रहा है।

एसबीआई कार्ड्स: पहले दिन 38 फीसदी आवेदन

उतार-चढ़ाव भरे बाजार में एसबीआई कार्ड्स ऐंड पेमेंट्स सर्विसेज के 10,350 करोड़ रुपये के आईपीओ निर्गम को सोमवार को पहले दिन अच्छी प्रतिक्रिया मिली। पहले दिन 38 फीसदी शेयरों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से काफी ज्यादा बोलियां छोटे निवेशकों से मिली हैं। शुक्रवार को कंपनी ने एंकर निवेशकों से करीब 2,800 करोड़ रुपये जुटाए हैं। संस्थागत निवेशकों के लिए एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ बुधवार को बंद होगा और गुरुवार को खुदरा एवं धनाढ्य निवेशकों के लिए बंद होगा।

सरकार ने 15 मार्च से प्याज निर्यात की अनुमति दी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि सरकार किसानों के हित में 15 मार्च से प्याज निर्यात की अनुमति देगी। उन्होंने ट्वीट किया कि इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने पिछले सप्ताह करीब छह महीने से प्याज के निर्यात पर जारी पाबंदी को हटाने का निर्णय किया। इसका कारण रबी फसल अच्छी रहने से कीमतों में तीव्र गिरावट की आशंका है। सब्जी की कीमत में तीव्र वृद्धि को देखते हुए निर्यात पर पाबंदी लगाई गई थी। अब प्याज के दाम स्थिर हो गए हैं और फसल भी अच्छी होने की उम्मीद है। पृष्ठ 13

एटीएफ की कीमतों में 10 फीसदी कटौती

विमान ईंधन के दामों में सोमवार को 10 फीसदी की भारी कटौती की गई। कोरोनावायरस फैलने की आशंका के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट के कारण यह कटौती की गई है। विमान ईंधन की कीमत में 6,590.62 रुपये प्रति किलोलीटर की कमी की गई है और दिल्ली में इसकी कीमत अब 56,859.01 रुपये प्रति किलोलीटर है। इससे पहले रविवार को बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलिंडर की कीमत में भी 53 रुपये की कटौती की गई थी। कटौती के बाद अब इसकी कीमत 805.50 रुपये हो गई है।

डीप फ्रीजर स्टार रेटिंग कार्यक्रम के दायरे में

बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने सोमवार को डीप फ्रीजर और हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर को स्टार लेबलिंग यानी स्टार रेटिंग कार्यक्रम के दायरे में लाने की घोषणा की। स्टार लेवल से पता चलता है कि कोई उपकरण बिजली खर्च के हिसाब कितना किफायती है। इससे केवल इन दो प्रकार के बिजली यंत्रों के इस्तेमाल में 2030 तक कुल 9 अरब यूनिट बिजली की बचत हो सकती है।

कोरोना के डर से ठिठका बाजार

785 अंक चढ़ने के बाद 153 अंक की गिरावट पर बंद हुआ सेंसेक्स

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 2 मार्च

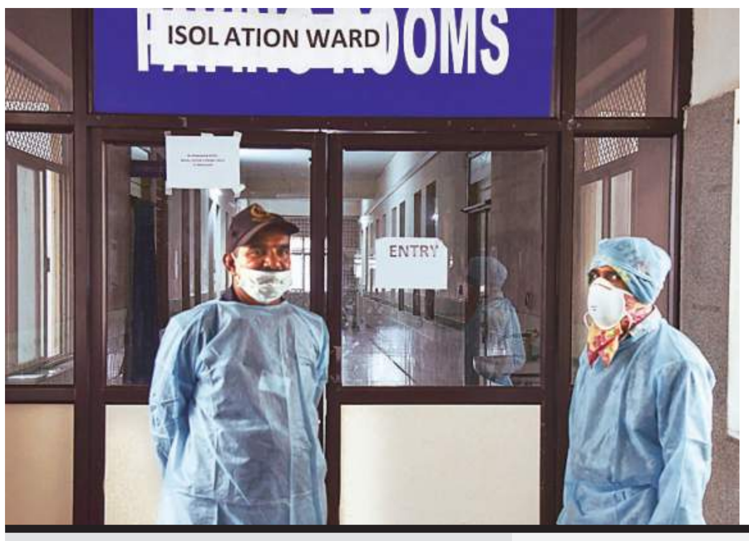

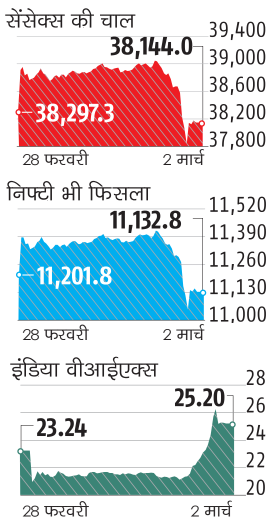

कोरोनावायरस की वजह से पिछले छह दिन से बाजार में आ रही गिरावट पर आज सुबह लगाम लगती दिखी और सेंसेक्स ने अच्छी तेजी दर्ज की। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश में कोरोनावायरस के दो नए मामले की पुष्टि की घोषणा से गिरावट फिर हावी हो गई।

एशियाई बाजारों से मिले अच्छे संकेत से घरेलू बाजार बढ़त पर खुला और सेंसेक्स 785 अंक तक चढ़ गया लेकिन दिल्ली और तेलंगाना में दो नए मामले की खबर से कारोबार के अंतिम घंटे में बिकवाली हावी हो गई और सेंसेक्स 511 अंक नीचे आ गया। उतार-चढ़ाव भरे दिन में कारोबार के अंत में सेंसेक्स 153 अंक गिरकर 38,144 पर बंद हुआ। 10 फरवरी के बाद से सेंसेक्स करीब 3,180 अंक टूट चुका है। निफ्टी भी 69 अंक नीचे 11,133 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 0.8 फीसदी नीचे 72.73 पर बंद हुआ, जो इसका 16 महीने का निचला स्तर है।

हालांकि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा कोरोनावायरस संकट से निपटने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की उम्मीद से एशियाई बाजार बढ़त पर बंद हुए। शुक्रवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरेमी पॉवेल ने अर्थव्यवस्था की मदद के लिए दरों में कटौती के संकेत दिए थे। बैंक ऑफ जापान ने कहा कि वह वित्तीय बाजार में पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करेगा।

बाजार के भागीदारों का कहना है कि केंद्रीय बैंकों की पहल सकारात्मक है लेकिन निवेशकों को इस बात का डर है कि भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो उसे काबू में करना कठिन हो सकता है।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सोने-चांदी में दिखी चमक

एमसीएक्स में सोना एवं चांदी में उछाल दर्ज की गई। सोना का अप्रैल वायदा 1.55 प्रतिशत बढ़कर 42,038 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। अंतराष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 1,600 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी का अप्रैल वायदा भी 1.1 प्रतिशत बढ़कर 44,897 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।

रुपये में आई नरमी

अमेरिका मुद्रा डॉलर के मुकाबले रुपया 72.73 पर बंद हुआ। मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि रुपया थामने के लिए आरबीआई कोई उपाय नहीं कर रहा है, जिससे लगता है कि अभी यह और नीचे जाएगा। कारोबारियों के अनुसार अगर रुपया लौटकर 72.50 पर नहीं आया तो यह आसनी से एक सप्ताह में 73.50 का स्तर पार कर सकता है।

विनिवेश लक्ष्य से पीछे रह सकती है सरकार

अरूप रायचौधरी
नई दिल्ली, 2 मार्च

- 10 हजार करोड़ रुपये की हो सकती है कमी
- दीपम ने ओएफएस की योजना टाली
- मार्च में कई ओएफएस थे प्रस्तावित
- बाजार में गिरावट से टाली योजना
- आईआरएफसी का आईपीओ और कुछ पुनर्खरीद भी इसी वर्ष

सरकार के लिए चालू वित्त वर्ष में 2019-20 में 65 हजार करोड़ रुपये के संशोधित विनिवेश लक्ष्य को हासिल करना संभव नहीं दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि बाजार में गिरावट को देखते हुए कई सार्वजनिक उपक्रमों की मार्च में प्रस्तावित बिक्री की पेशकश (ओएफएस) को टाल दिया गया है। इनमें सेल, एनएमडीसी, पीएफसी लिमिटेड, कोल इंडिया, इरकॉन, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स और कई अन्य कंपनियां शामिल हैं। वित्त मंत्रालय के अनुमानों के मुताबिक विनिवेश लक्ष्य 10 हजार करोड़ रुपये कम रह सकता है।

सूत्रों के मुताबिक इस महीने कुछ ही सरकारी कंपनियों में विनिवेश की संभावना है। इनमें एनटीपीसी द्वारा टीएचडीसी लिमिटेड और नीपको का अधिग्रहण, आईआरएफसी लिमिटेड का प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम और कुछ सरकारी उपक्रमों में पुनर्खरीद शामिल है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'हमने कई कंपनियों के ओएफएस की योजना बनाई थी और हम इनमें से कुछ को मार्च में निपटाना चाहते थे। हमने इसके लिए रोडशो भी आयोजित किए थे। लेकिन कोरोनावायरस और अन्य वैश्विक कारणों से बाजार में गिरावट का दौर है। ऐसी स्थितियों में हम बाजार में नहीं जा सकते हैं।' वित्त मंत्रालय एनटीपीसी द्वारा टीएचडीसी और नीपको के अधिग्रहण से 15 हजार करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद कर रहा है। साथ ही आईआरएफसी लिमिटेड के प्रस्तावित आईपीओ और कुछ पुनर्खरीद से 5 हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना है।

विनिवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने अब तक करीब 35 हजार करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसमें अगर 20 हजार करोड़ रुपये की रकम और जुड़ती है तो यह 55 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी। इस तरह केंद्र अपने संशोधित लक्ष्य से 10 हजार करोड़ रुपये दूर रह जाएगा।

सरकार ने आम बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया था जिसे बाद में संशोधित कर 65 हजार करोड़ रुपये किया गया। 2020-21 के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के लिए कर राजस्व और कुल खर्च अनुमानों में भी कटौती की थी और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 3.3 फीसदी से बढ़ाकर 3.8 फीसदी कर दिया गया था।

अधिकारी ने कहा कि आईआरएफसी का आईपीओ इस तरह की बाजार परिस्थितियों में भी इसी महीने आएगा। ओएफएस अब 31 मार्च के बाद लाए जाने की उम्मीद है।' इसका मतलब है कि वे 2020-21 के 2.1 लाख करोड़ रुपये के बजटीय विनिवेश लक्ष्य में योगदान देंगे। पिछले सप्ताह केंद्र ने राइट्स लिमिटेड में अपनी 10 फीसदी हिस्सेदारी ओएफएस के जरिये बेच दी थी। यह इश्यू बुरी तरह फ्लॉप रहा।

वायरस से कराह रहा पर्यटन उद्योग

अनीश फडणीस
मुंबई, 2 मार्च

- कई ट्रैवल फर्मों ने वेतन वृद्धि टाली, नई भर्तियों पर लगाई रोक
- कुछ विमानन कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन में भी की कटौती
- ऑनलाइन यात्रा पोर्टल एक्सपीडिया दुनिया भर में कर रही 3,000 छंटनी
- विदेशी यात्रा की बुकिंग में भारी गिरावट

कोरोनावायरस के कहर का पर्यटन क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ा है। ऐसे में कई ट्रैवल कंपनियां अपने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि टाल दी है और नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा के लिए बुकिंग पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, वहीं यूरोप में भी वायरस फैलने से बुकिंग रद्द होने की आशंका है। यूरोप के लिए सामूहिक यात्रा की शुरुआत आम तौर पर शैक्षणिक सत्र खत्म होने के बाद अप्रैल से शुरू होती है।

थॉमस कुक ने खर्चे कम करने के लिए कर्मचारियों की वेतन वृद्धि टाल दी है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को अप्रत्याशित बाजार की स्थिति का हवाला देकर वेतन वृद्धि नहीं करने के निर्णय के बारे में सूचित कर दिया है। इस बारे में पुष्टि के लिए थॉमस कुक को ईमेल किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हालांकि पिछले हफ्ते शेयर पुनर्खरीद की सूचना में कंपनी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में नरमी और कोरोनावायरस की वजह से मांग कम होने से कारोबार पर असर पड़ा है। कंपनियां नई नियुक्तियां नहीं कर रही हैं और अन्य खर्चों में भी कटौती कर रही हैं। अकबर ग्रुप के मुख्य परिचालन अधिकारी अमेय अमलाडी ने कहा, 'भर्तियां लगभग रुक गई हैं और बहुत जरूरत होने पर ही नई नियुक्ति की जा रही है।' स्टिक ट्रैक ग्रुप को निदेशक इशा गोयल ने कहा, 'हमने बुनियादी ढांचे के उन्नयन का काम रोक दिया है और गैर-जरूरी खर्चे कम करने के लिए कंपनी के कार्यक्रम भी टाले जा रहे हैं।'

कोरोना के प्रसार की वजह से दुनिया भर में विमानन और पर्यटन क्षेत्र को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने विमानन कंपनियों को 30 अरब डॉलर राजस्व के नुकसान का अनुमान लगाया था और इनमें सबसे ज्यादा नुकसान चीन के लिए उड़ान भरने वाली विमानन कंपनियों को हो रहा है। इटली, कोरिया और जापान में भी बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करने की खबर है।

(शेष पृष्ठ 16 पर)

वाहन उद्योग की भी बढ़ी चिंता

मंदी और उत्सर्जन मानकों से जुड़ी चुनौती से जूझ रहे भारत के वाहन उद्योग को अब कोरोनावायरस की महामारी के प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग संगठन सायम के अध्यक्ष राजन वढेरा को आशंका है कि मार्च का महीना खराब रहेगा और कुल बिक्री सालाना आधार पर 25 से 30 प्रतिशत तक घट सकती है।

उन्होंने कहा कि बीएस-6 उत्सर्जन मानक लागू होने से पहले की मार्च की अवधि उतार-चढ़ाव भरी रहने की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी, अब कोविड-19 ने भी चीन से प्रमुख कलपुर्जों (खासकर बीएस-6 वाहनों के लिए) की आपूर्ति प्रभावित की है, जिससे चिंता और बढ़ गई है। वढेरा ने कहा, 'वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इनके लिए चीन से कलपुर्जों की खरीद एक बड़ी चुनौती होगी।' पृष्ठ 3

जीएसटी वसूली लक्ष्य से चूकेगी दिल्ली सरकार!

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 2 मार्च

- फरवरी तक जीएसटी वसूली में 10 फीसदी वृद्धि
- बजट लक्ष्य पूरा करने के लिए 16 फीसदी वृद्धि होनी चाहिए

दिल्ली सरकार चालू वित्त वर्ष के बजट में निर्धारित जीएसटी वसूली लक्ष्य से चूक सकती है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जीएसटी वसूली 16 फीसदी से ज्यादा बढ़नी चाहिए। लेकिन अब तक वसूली में वृद्धि दर करीब 10 फीसदी रही है जबकि वित्त वर्ष पूरा होने में महज एक महीना बचा है। ऐसे में लक्ष्य पूरा करने के लिए एक महीने में औसत मासिक जीएसटी वसूली की दोगुनी राशि वसूलनी होगी जो मुश्किल लग रहा है। दिल्ली में फरवरी महीने में जीएसटी वसूली 12 फीसदी बढ़कर 1,918 करोड़ रुपये रही।

दिल्ली जीएसटी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2019-20 में फरवरी तक दिल्ली सरकार को जीएसटी व आईजीएसटी मिलाकर करीब 19,230 करोड़ रुपये मिले हैं, जो पिछले साल की समान अवधि में करीब 17,600 करोड़ रुपये था। इस तरह जीएसटी वसूली में वृद्धि दर 10 फीसदी से भी नीचे चल रही है। बजट में चालू वित्त वर्ष के जीएसटी वसूली का लक्ष्य 22,620 करोड़ रुपये है। इसे पूरा करने के लिए अंतिम महीने में करीब 3,400 करोड़ रुपये संग्रह होने चाहिए जबकि अब तक प्राप्त कुल जीएसटी के आधार पर औसत मासिक वसूली 1,750 करोड़ रुपये है।

मनोरंजन बाजार में क्षेत्रीय चैनलों की बयार

किसका, कितना हिस्सा

नेटवर्क	दर्शकों का हिस्सा (2019,%) हिंदी	दर्शकों का हिस्सा (2019,%) क्षेत्रीय	चैनल हिंदी	चैनल क्षेत्रीय	राजस्व (करोड़ रुपये) वित्त वर्ष 19
सन	0	10.3	0	32	3,782
डिज़्नी स्टार	8.7	9.9	18	22	11,956
ज़ी	9.3	9.5	17	23	7,934
वायकॉम 18	3.4	2.9	5	14	3,667
सोनी	5.9	2.5	11	2	6,309

देश भर में दर्शकों की संख्या2+

स्रोत : बार्क इंडिया, कंपनी पंजीयक और कंपनियां

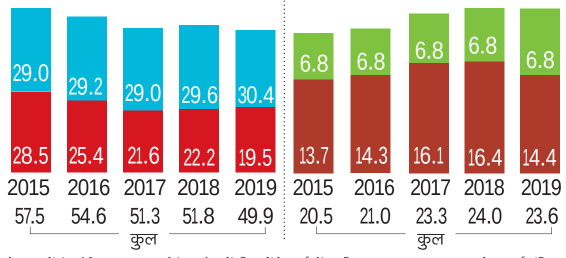

देश भर में 4+ / 2+ सामान्य मनोरंजन चैनलों, फिल्मों के द र्शकों का हिस्सा (%)

स्रोत : बार्क इंडिया

वनिता कोहली-खांडेकर
मुंबई, 2 मार्च

पंजाबियत क्या है? पंजाबी दर्शकों को सबसे अच्छा क्या लगता है? ज़ी ने इसी साल पंजाबी चैनल शुरू किया है। ज़ी एंटरटेनमेंट की चीफ कंज्यूमर ऑफिसर प्रत्यूषा अग्रवाल ने कहा, 'पंजाब के दर्शकों की पसंद को समझने के लिए हमने 2018 में तीन महीने वहां बिताए थे।' यही वजह है कि ज़ी पंजाबी चैनल पर सेना के लिए प्यार, विभाजन की कहानियों और पंजाबी महिलाओं की ताकत से जुड़े कार्यक्रमों को तरजीह दी गई। पंजाब में मनोरजन चैनलों का बाजार अपेक्षाकृत छोटा है और ज़ी पंजाबी का दावा है कि उसने एक तिहाई बाजार पर अपनी पकड़ बना ली है। इसी तरह जनवरी में शुरू हुए भोजपुरी चैनल ज़ी बायस्कोप, फरवरी में तमिल चैनल ज़ी तिरई और जल्दी ही शुरू होने वाले कन्नड चैनल ज़ी पिच्चर के लिए भी ऐसा ही किया गया। इन चैनलों की औपचारिक शुरुआत से पहले फिल्मों के बारे में क्षेत्रीय दर्शकों की पसंद के बारे में गहन पड़ताल की गई। ज़ी पिच्चर की शुरुआत से ज़ी के क्षेत्रीय चैनलों की संख्या 24 पहुंच जाएगी जो 2017 में 18 थी।

हालांकि बहुभाषी चैनलों की इस होड़ में ज़ी अकेली कंपनी नहीं है। वायकॉम18 ने पिछले साल कलर्स गुजराती सिनेमा और कलर्स बांग्ला सिनेमा शुरू किया था। इस तरह उसके क्षेत्रीय चैनलों की संख्या 14 हो गई है जिसमें एचडी चैनल भी शामिल हैं। डिज्नी के मालिकाना हक वाली स्टार इंडिया ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से अपने क्षेत्रीय चैनलों की संख्या बढ़ाई है। 2017 में उसके पास 14 क्षेत्रीय चैनल थे जो अब 22 हो गए हैं। प्रसारक कंपनियों के कई खेल चैनल अब तमिल, तेलुगू और दूसरी भाषाओं में भी प्रसारण करते हैं। स्टार इंडिया के क्षेत्रीय एंटरटेनमेंट चैनलों के मुख्य कार्याधिकारी केविन वाज कहते हैं, 'पिछले तीन साल में क्षेत्रीय बाजारों में भारी बदलाव आया है।'

यह बात सही है और इसके कारण खोजना मुश्किल नहीं है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के आंकड़ों के मुताबिक देश में 83.6 करोड़ लोग टीवी देखते हैं। इनमें से करीब 76.2 करोड़ लोग नियमित तौर पर औसतन एक से चार घंटे टीवी देखते हैं। 74,000 करोड़ रुपये का टीवी उद्योग पिछले कुछ वर्षों से दोहरे अंकों में बढ़ रहा है।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

खबरों में रहे स्टॉक

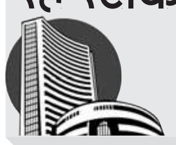

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनैंस

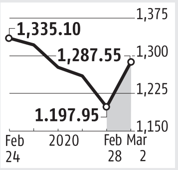

ऋण प्रतिभूतियों के जरिये रकम जुटाने की योजना

₹ 1,197.95 पिछला बंद भाव
₹ 1,287.55 आज का बंद भाव
▲ 7.48 %

बजाज ऑटो

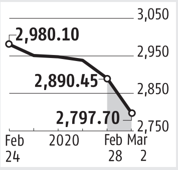

फरवरी में कुल बिक्री 10 फीसदी घटी

₹ 2,890.45 पिछला बंद भाव
₹ 2,797.70 आज का बंद भाव
▼ 3.21 %

एस्कॉर्ट्स

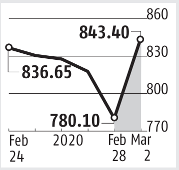

फरवरी में ट्रैक्टरों की बिक्री 16 फीसदी बढ़ी

₹ 780.10 पिछला बंद भाव
₹ 843.40 आज का बंद भाव
▲ 8.11 %

ऐफल (इंडिया)

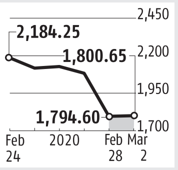

यूरोप की कंपनी मीडियामार्ट के अधिग्रहण के लिए करार पर हस्ताक्षर

₹ 1,794.60 पिछला बंद भाव
₹ 1,800.65 आज का बंद भाव
▲ 0.33 %

आईनॉक्स लेजर

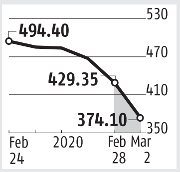

एसऐंडपी बीएसई 500 सूचकांक में सबसे अधिक गिरने वाला शेयर

₹ 429.35 पिछला बंद भाव
₹ 374.10 आज का बंद भाव
▼ 12.87 %

संक्षेप में

मंदी से कर्ज अदायगी में चूक की आशंका

अर्थव्यवस्था में लंबे समय से जारी सुस्ती के बीच कुल 10.52 लाख करोड़ रुपये के बराबर कंपनी कर्ज मेंचूक की आशंका है। इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च ने एक रिपोर्ट में कहा कि कंपनियों का ऋण दबाव में रह सकता है। इसका कारण अर्थव्यवस्था में लंबे समय से जारी सुस्ती है। कंपनियों के कम-से-कम 10.52 लाख करोड़ रुपये के कर्ज लौटाने में अगले तीन साल में चूक की आशंका है। यह कंपनियों के कुल कर्ज का करीब 16 प्रतिशत है। रिपोर्ट में निजी क्षेत्र की शीर्ष 500 कंपनियों द्वारा जुटाए गए कर्ज के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। इसमें इन कंपनियों के उत्पादक और गैर-उत्पादक परिसपंत्तियों का आकलन किया गया। *भाषा*

एनबीसीसी को बीएचईएल से मिला ऑर्डर

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी ने कहा है कि उसे झारखंड में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से 64.83 करोड़ रुपये का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। एनबीसीसी ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज को भेजी नियामकीय सूचना में इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि भेल से मिले इस ऑर्डर को कंपनी इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण प्रारूप के तहत पूरा करेगी। कंपनी ने कहा है कि ऑर्डर के तहत वह झारखंड में उत्तरी करणपुरा एसटीपीपी स्थित 660 मेगावाट प्रत्येक की तीन इकाइयों के लिए चिमनी बनाने का काम करेगी। *भाषा*

कोक का नं3 बाजार होगा भारत

कंपनी अगले पांच वर्षों के दौरान भारत में बिक्री दो अंकों में बढ़ाने की कर रही तैयारी

विवेट सुजन पिंटो
मुंबई, 2 मार्च

विश्व की सबसे बड़ी बेवरिजेस कंपनी कोका कोला भारत को अपना तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक बाजार बनाना चाहती है। कंपनी के वैश्विक मुख्य कार्याधिकारी जेम्स क्विंसी ने आज यह बात कही। भारत की अपनी तीसरी यात्रा के दौरान 55 वर्षीय क्विंसी ने संकेत दिया कि भारतीय कारोबार की बिक्री कैलेंडर वर्ष 2019 में 1 अरब इकाई तक पहुंच गई।

क्विंसी ने कहा कि अटलांटा की इस कंपनी की स्थानीय इकाई की नजर अब पांच वर्षों के भीतर बिक्री को बढ़ाकर 2 अरब इकाई करने पर है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब घरेलू बाजार खपत में गिरावट जैसी समस्या से जूझ रहा है और उसमें सुधार के फिलहाल कोई संकेत नहीं दिख रहा है।

क्विंसी ने कहा कि खपत में लघु अवधि की गिरावट से वृद्धि के लिए कंपनी की दीर्घावधि योजना प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा, 'कोका कोला कंपनी के लिए भारत एक रणनीतिक बाजार है। इसने वैश्विक नतीजों में लगातार दमदार योगदान किया है और यहां वृद्धि की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।' उन्होंने कहा, 'हम स्थानीयकरण पर जोर देते हुए एक समग्र बेवरिजेस कंपनी बनने के लिए बदलाव कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान हमारे बेवरिजेस पोर्टफोलियो में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है।'

कोका कोला के वैश्विक बाजारों में भारत का स्थान फिलहाल पांचवां है और यह जापान से आगे है। जबकि अमेरिका, मेक्सिको, चीन और ब्राजील कोका कोला के शीर्ष चार वैश्विक बाजार हैं। जहां तक उत्पाद पोर्टफोलियो का सवाल है तो भारत में कोका कोला के पास कार्बोनेटेड और गैर-कार्बोनेटेड दोनों तरह के शीतल पेय मौजूद हैं। क्विंसी ने कहा कि इसमें दमदार रफ्तार के साथ वृद्धि हो रही है।

क्विंसी ने कहा कि बुलबुले वाले ड्रिंक्स और जूस के अलावा कोका कोला अब बेहतर हाइड्रेशन, घुलनशील और कम कैलरी वाले ड्रिंक्स पर भी दांव लगा रही है।

कंपनी पर नजर रखने वाले विश्लेषकों का कहना है कि कोका कोला का भारतीय कारोबार कम से कम पिछले दो वर्षों से लगातार मात्रात्मक बिक्री में वृद्धि दर्ज कर रहा है। कार्बोनेटेड और गैर-कार्बोनेटेड उत्पाद पोर्टफोलियो से बिक्री को रफ्तार मिल रही है। नियामकीय खुलासे के अनुसार, कोका कोला के घरेलू बॉटलिंग एवं मार्केटिंग कारोबार का कुल राजस्व वित्त वर्ष 2018-19 में 12 से 13 हजार करोड़ रुपये रहा।

दिसंबर में कोका कोला ने उत्तर भारत में अपने बॉटलिंग कारोबार को पुनगर्ठित करते हुए चार क्षेत्र अपने मौजूदा बॉटलरों को हस्तांतरित कर दिए थे। कंपनी ने उन कयासों का खंडन किया था कि वह भारत में बॉटलिंग कारोबार से बाहर होने जा रही है। कंपनी ने कहा था कि वह भारत में अपने कारोबार के सभी पहलुओं पर निवेश जारी रखेगी।

रफ्तार में कोका कोला

- कोका कोला के वैश्विक बाजारों में भारत का स्थान फिलहाल पांचवां है
- भारतीय इकाई की बिक्री कैलेंडर र्ष 2019 में 1 अरब इकाई तक हुई
- अगले 5 वर्षों में बिक्री को बढ़ाकर 2 अरब इकाई करने पर नजर

कोटक फंड ने ली जिंदल स्टेनलेस में हिस्सेदारी

अदिति दिवेकर
मुंबई, 2 मार्च

कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्रबंधित कोटक स्पेशल सिचुएशंस फंड (केएसएसएफ) ने आज कर्ज व इक्विटी के जरिए जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में 500 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया। कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने एक विज्ञप्ति में कहा, इससे स्टेनलेस स्टील उत्पादक को कंपनी कर्ज पुनर्गठन (सीडीआर) प्रक्रिया से बाहर निकलने में मदद मिलेगी क्योंकि निवेश से कंपनी बैंकों को कर्ज का पुनर्भुगतान कर पाएगी।

कोटक स्पेशल सिचुएशंस फंड एक अरब डॉलर का फंड है और वह भारत में विशेष परिस्थितियों में निवेश करता है। इस सौदे के तहत केएसएसएफ ने जिंदल स्टील के लेनदारों से इक्विटी शेयर खरीदे हैं और सीडीआर पैकेज के तहत लेनदारों के बकाए वैकल्पिक परिवर्तनीय भुनाए जाने योग्य तरजीही शेयर के पुनर्भुगतान के लिए कंपनी के ऋणपत्र में निवेश किया है।

इस लेनदेन के पूरा होने के बाद केएसएसएफ के पास जिंदल स्टेनलेस की करीब पांच फीसदी हिस्सेदारी होगी। कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड में कोटक स्पेशल सिचुएशंस फंड के मुख्य कार्याधिकारी ई. कारा ने कहा, कंपनी की पांच फीसदी हिस्सेदारी के जरिए हम जिंदल स्टेनलेस के साथ साझेदारी से हम खुश हैं और सीडीआर से बाहर निकलने के लिए हम कंपनी को वित्तीय सुविधा मुहैया करा रहे हैं।

उन्होंने कहा, जिंदल स्टेनलेस में हमारा निवेश अदभुत समाधान के जरिये कंपनी के क्रेडिट लाइफसाइकल में भागीदारी के हमारे मकसद के मुताबिक है। सीडीआर से बाहर निकलकर जिंदल स्टेनलेस अब बढ़त की राह तैयार कर सकती है और प्रतिस्पर्धी शर्तों पर वित्तीय बाजार से संपर्क कर सकती है।

इस बारे में जिंदल स्टेनलेस के अधिकारी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हुए। 31 मार्च 2019 को 1.5 फीसदी कर्ज-इक्विटी अनुपात के साथ जिंदल स्टेनलेस का शुद्ध कर्ज 3,645 करोड़ रुपये है। कर्ज का स्तर हालांकि वित्त वर्ष 2014 के 12,000 करोड़ रुपये से काफी नीचे आया है, लेकिन नकदी व नकदी समकक्ष वित्त वर्ष 2019 में महज 47.5 करोड़ रुपये रह गया है।

कोरोनावायरस के डर से ठिठका शेयर बाजार

पृष्ठ 1 का शेष...

इस बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर में इटली के एक पर्यटक में कोरोनावायरस की जांच पॉजिटिव पाई गई है। इसके बाद डीजीसीए ने कहा कि इटली और ईरान से आने वाले सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से पूरी जांच की जाए। सोमवार तक दुनिया भर में कारोना की वजह से 3,000 लोगों के मारे जाने की खबर है। अवेंडस कैपिटल अल्टरनेट स्ट्रैटजीज के मुख्य कार्याधिकारी एंड्रयू हॉलैंड ने कहा, 'बाजार को समझ नहीं आ रहा है कि कोरोना को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऐसे में अगर रात भर कोई बुरी खबर नहीं आती है तो बाजार अगले दिन वापसी भी कर सकता है।'

भारत पहले ही आर्थिक नरमी और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है और कोरोना संकट गहराने से व्यापक असर पड़ सकता है। कंपनियों की कम कमाई, एनबीएफसी संकट की वजह से उधारी गतिविधियों में नरमी से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। दूसरी ओर नागरिकता कानून के विरोध से तनाव बना हुआ है और दिल्ली में हुए दंगे में 46 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। विश्लेषकों ने कहा कि भारत सरकार को कोरोना संक्रमण को रोकने के हरसंभव प्रयास करने चाहिए और साथ ही चीन एवं दक्षिण कोरिया में उत्पादन बाधित होने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

मार्सेलस इन्वेस्टमेंट्स के संस्थापक सौरभ मुखर्जी ने कहा, 'फॉर्च्युन 500 में शामिल सभी कंपनियां अपने उत्पादन को विविधीकृत करने की संभावना तलाशेंगी, ऐसे में हमें विनिर्माण के इस अवसर का लाभ उठाने पर ध्यान देना चाहिए।'

तीन सेक्टर सूचकांकों को छोड़कर बीएसई के अन्य सभी सूचकांक गिरावट पर बंद हुए। धातु और तेल एवं गैस सूचकांक में सबसे ज्यादा 2-2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स में शामिल दो-तिहाई शेयर गिरावट पर बंद हुए। भारतीय स्टेट बैंक में सबसे ज्यादा 5 फीसदी और टाटा स्टील में 4.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 1,355 करोड़ रुपये के शेयरों की बिकवाली की, वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,139 करोड़ रुपये की लिवाली की।

कॉग्निजेंट का डिजिटल समझ पर जोर

कॉग्निजेंट प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ज्यादा सौदे पाने के प्रयास में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की अच्छी समझ रखने वाले बिक्री कर्मियों को नियुक्त करने पर ध्यान दे रही है। लगभग 500 लोगों की मजबूत बिक्री टीम तैयार करने की प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी एसएएएस कंपनियों के साथ काम कर चुके लोगों को पहले ही नियुक्त कर चुकी है। कॉग्निजेंट डिजिटल बिजनेस के अध्यक्ष मैलकोम फ्रैंक ने कहा, 'कंपनी द्वारा नियुक्त किए जा रहे 500 लोगों में ज्यादातर डिजिटल समझ रखने वाले लोग शामिल हैं। हमारे पास ऐसे सेल्स स्पेशलिस्ट हैं, जो एमेजॉन की एडब्ल्यूएस, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जैसी प्रमुख एसएएएस कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं।' फ्रैंक ने यह भी कहा कि डिजिटल स्पेस में मिल रहे सौदे ज्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन परियोजना-आधारित हैं जिनमें समय के साथ इजाफा होता है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी सेगमेंट में उभर रहे अवसरों का लाभ उठाने के लिए लगभग 25,000 कर्मियों को नियुक्त या पुन: प्रशिक्षित करने की भी योजना बनाई है। *बीएस*

बेरिंगर का जोर मधुमेह दवा पर

सोहिनी दास
मुंबई, 2 मार्च

जर्मनी की प्रमुख औषधि कंपनी बेरिंगर इंगेलहाइम ने भारत के अपने मधुमेहरोधी पोर्टफोलियो में पिछले पांच वर्षों के दौरान 45.4 फीसदी की चक्रवृद्धि दर से विकास की है। अब इस श्रेणी में कंपनी की प्रमुख दवा की पेटेंट अवधि खत्म होने जा रही है और इसे देखते हुए कंपनी ने द्विआयामी रणनीति तैयार की है।

अपनी नई रणनीति के तहत कंपनी मौजूदा आधार को सुदृढ़ करते हुए पेटेंट की अवधि खत्म होने से पहले कारोबार को दोगुना करने और अगले चरण की वृद्धि को रफ्तार देने के लिए वैश्विक बाजार में उतारी जाने वाली नोबल दवाओं को भारत लाने की भी योजना बनाई है।

बेरिंगर इंगेलहाइम की मधुमेहरोधी दो प्रमुख मॉलिक्यूल-लिनैग्लिपटिन और इम्पैग्लिग्लोजिन के लिए पेटेंट की अवधि क्रमश: 2023 और 2025 में खत्म हो जाएगी। एआईओसीडी अवाक्स के आंकड़ों के अनुसार, उसकी इम्पैग्लिफ्लोजिन ब्रांड जार्डिएंस ने पिछले पांच वर्षों के दौरान 157.8 फीसदी की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की है। बेरिंगर ने अपनी मधुमेह दवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए बिक्री प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाकर 570 कर दिया है। कंपनी के कुल कारोबार में उसके मधुमेह पोर्टफोलियो का योगदान करीब 75 फीसदी है।

बेरिंगर इंगेलहाइम इंडिया के प्रबंध निदेशक शरद त्यागी ने कहा, 'हमारी मंशा बाजार के मुकाबले कहीं अधिक रफ्तार के साथ वृद्धि करने की है। पेटेंट की अवधि खत्म होने जा रही है जो हमारे लिए एक महत्त्वपूर्ण घटना है। हम रणनीतिक आकलन पर काम कर रहे हैं और हमारी नजर विल्डाग्लिपटिन की पेटेंट अवधि और बाजार में विभिन्न कंपनियों की रणनीतियों पर भी है।' जब किसी दवा की पेटेंट अवधि खत्म हो जाती है तो आमतौर पर उसके बाजार में विस्तार होता है क्योंकि दाम घटने होने के कारण तमाम डॉक्टर रोगियों को उस दवा की सलाह देने लगते हैं। त्यागी ने कहा कि लिनेग्लिपटिन की पेटेंट अवधि खत्म होने तक विल्डाग्लिपटिन और सिटाग्लिपटिन (दोनों मधुमेह की दवा) की पेटेंट अवधि भी खत्म हो जाएगी और वास्तव में बाजार काफी बड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा, 'उस लिहाज से हमें यह देखने की जरूरत है कि हमारी कीमत और वैज्ञानिक लाभ की क्या स्थिति है। चाहे डॉक्टर हो अथवा रोगी इस ब्रांड ने सभी हितधारकों के बीच खुद को स्थापित किया है और उनमें भरोसा जगाया है।'

कंपनी भारत में महज 10 दवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिनमें 5 मधुमेह की, दो कैंसर की और कुछ सांस की बीमारियों की दवाएं हैं। इसके अलावा कुछ दवाएं हृदयरोग एवं हृदयाघात की रोकथाम से संबंधित हैं।

त्यागी ने कहा, 'जहां तक ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं का सवाल है तो हम ब्रांडों की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। हमारी योजना बिल्कुल स्पष्ट है कि हम अपने नवोन्मेषी दवाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे।'

वाहनों पर कोरोनावायरस का प्रकोप

इस महीने भी 30 फीसदी घटेगी बिक्री

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 2 मार्च

वाहन निर्माता कर रहे निपटने की तैयारी

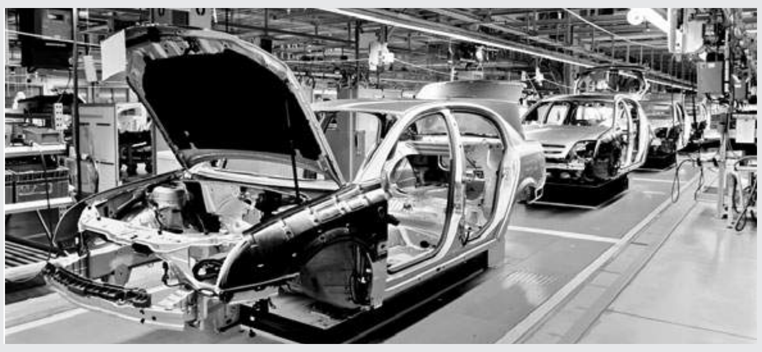

- वाणिज्यिक वाहन, दोपहिया निर्माता होंगे ज्यादा प्रभावित
- वाहन कलपुर्जा आयात में चीन का 26 प्रतिशत का योगदान है
- इस महामारी से बीएस-6 मॉडलों की आपूर्ति हो सकती है प्रभावित
- मार्च में वाहनों की बिक्री में 25 से 30 प्रतिशत कमी आने की आशंका

मंदी और उत्सर्जन मानकों से जुड़ी चुनौती से जूझ रहे भारत के वाहन उद्योग को अब कोरोनावायरस की महामारी के प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। यह वायरस दुनिया में तेजी से फैल रहा है।

उद्योग संगठन सायम के अध्यक्ष राजन वढेरा को आशंका है कि मार्च का महीना खराब रहेगा और कुल बिक्री सालाना आधार पर 25-30 प्रतिशत तक घट सकती है।

उन्होंने कहा कि बीएस-6 उत्सर्जन मानक लागू होने से पहले की मार्च की अवधि उतार-चढ़ाव भरी रहने की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी, अब कोविड-19 ने भी चीन से प्रमुख कलपुर्जों (खासकर बीएस-6 वाहनों के लिए) की आपूर्ति प्रभावित की है, जिससे चिंता और बढ़ गई है।

वढेरा ने कहा, 'वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इनके लिए चीन से कलपुर्जों की खरीद एक बड़ी चुनौती होगी।' ऑटो कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एक्मा) के अध्यक्ष दीपक जैन के अनुसार भारत के वाहन कलपुर्जा उद्योग ने 17 अरब डॉलर के कलपुर्जों का आयात किया। इसमें चीन का योगदान 4.5 अरब डॉलर था।

वढेरा का कहना है कि चीन बीएस-6 में अन्य देशों से आगे है, जिसे देखते हुए कई वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं ने कलपुर्जे विकसित करने के लिए इस देश का इस्तेमाल किया। देश में परिचालन बहाल करने में फैक्टरियों को अभी कुछ और वक्त लगेगा। इनमें से कई फैक्टरियां अपने सिर्फ एक-तिहाई कर्मियों के साथ आधी क्षमता से भी कम के साथ परिचालन कर रही हैं। जैन का मानना है, 'चीन को वैश्विक बाजारों की जरूरतें पूरी करनी हैं। इसलिए, उत्पादन बहाल होने पर उन्हें राशन आपूर्ति करनी होगी।' इसके अलावा, एयर टर्मिनलों और बंदरगाहों पर माल ढुलाई प्रभावित हुई है। इस सबका लॉजिस्टिक के संदर्भ में व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब अर्थव्यवस्था में मंदी से वाहन बिक्री पर असर दिखा है। मध्यम एवं भारी ट्रकों की बिक्री पर दबाव महसूस किया गया है। कमजोर आर्थिक गतिविधि की वजह से जून 2019 से ही इस बिक्री पर दबाव बना हुआ है।

सभी ट्रक निर्माताओं ने अपने वाहनों की खेपों में पिछले महीने एक साल पहले की तुलना में 45 प्रतिशत से ज्यादा की कमी दर्ज की, क्योंकि उन्होंने डीलरों को खेपों में कमी की और 1 अप्रैल से लागू हो रहे नए उत्सर्जन मानकों से पहले इन्वेंट्री वृद्धि को लेकर सतर्क बने रहे।

एक्मा के जैन का कहना है, दोपहिया सेगमेंट में भी चिंता बरकरार है। जहां यात्री वाहन सख्त उत्सर्जन प्रौद्योगिकी की चुनौती से जूझ रहे हैं, वहीं कई दोपहिया निर्माता इस महीने बीएस-6 मॉडल पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। जैन ने कहा, 'मार्च में दिख रहा उतार-चढ़ाव, हमारे अनुमान के मुकाबले काफी ज्यादा रह सकता है।'

फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रबंध निदेशक संजीव वासदेव भी चिंतित हैं। उन्होंने कहा, 'कोरोना का प्रभाव इस महीने से ज्यादा महसूस किया जाएगा और उन कुछ निर्माताओं के लिए यह बेहद चुनौतीपूर्ण होगा जिन्होंने बीएस-6 पेशकश की योजना बनाई है।'

फरवरी में जारी रही वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में गिरावट

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 2 मार्च

वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री

कंपनी	फरवरी 2020	फरवरी 2019	बदलाव (% में
टाटा मोटर्स	25,572	39,111	-35
अशोक लीलैंड	10,612	17,352	-39
एमऐंडएम	15,856	21,154	-25
बजाज ऑटो	21,871	35,183	-38
वीईसीवी	3,875	5,337	-27
कुल	77,786	1,18,137	-34

*मध्यम व भारी वाणिज्यिक वाहन, आईसीवी समेत

वाणिज्यिक वाहन उद्योग में उदासी बनी हुई है और कंपनियां बिक्री में गिरावट का सामना कर रही हैं। अग्रणी वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं की संचयी बिक्री फरवरी 2020 में एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले करीब 35 फीसदी घट गई।

उद्योग के प्रतिनिधियों ने कहा कि स्थिति में जल्द सुधार शायद ही गोगा क्योंकि कारोबारी गतिविधियों में नरमी और उपभोक्ताओं के कम खर्च के कारण भारत की आर्थिक गतिविधियां अभी रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। ऐक्सल लोड के नियमों, नकदी संकट, जीएसटी, बीएस-4 की इन्वेंट्री और आर्थिक मंदी आदि से कंपनियों की बिक्री पर दबाव है।

टाटा मोटर्स की देसी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री फरवरी 2020 में एक साल पहले के 39,11 वाहनों के मुकाबले घटकर 25,572 वाहन रह गई। यह गिरावट मध्यम व भारी वाणिज्यिक वाहनों की अगुआई में हुई, जहां बिक्री पिछले साल के 12,437 वाहनों के मुकाबले 46 फीसदी घटकर 6,739 वाहन रह गई। इस दौरान निर्यात पर भी चोट पड़ी।

टाटा मोटर्स के अध्यक्ष (वाणिज्यिक वाहन कारोबार) गिरीश वाघ ने कहा, फरवरी में खुदरा बिक्री थोक से 37 फीसदी ज्यादा रही और इससे कंपनी को स्टॉक अब तक के निचले स्तर पर लाने में मदद मिली। मध्यम व भारी वाणिज्यिक वाहनों की खुदरा बिक्री पिछले महीने 23 फीसदी बढ़ी क्योंकि वाहनों के बेड़ा खरीदने वालों ने खरीदारी में इजाफा किया।

अशोक लीलैंड ने मध्यम व भारी वाणिज्यिक वाहनों की देसी बिक्री में 47 फीसदी की गिरावट दर्ज की और यह एक साल पहले के 12,621 वाहन के मुकाबले 6,745 वाहन रह गई। ट्रकों की बिक्री 58 फीसदी घटकर 4,706 रह गई, वहीं देसी बसों की बिक्री 36 फीसदी बढ़कर 2,039 रही। कुल देसी बिक्री फरवरी में 39 फीसदी घटकर 10,612 वाहन रह गई।

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 25 फीसदी घटकर फरवरी में 15,856 वाहन रह गई। मध्यम व भारी वाणिज्यिक वाहन के क्षेत्र में महिंद्रा ने फरवरी में 436 वाहन बेचे। फरवरी में निर्यात 1,839 वाहनों का रहा। महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा, फरवरी में वाहनों का थोक वॉल्यूम आपूर्ति शृंखला में अवरोध और बीएस-6 उत्सर्जन नियमों की ओर बढ़ने के कारण काफी कम रहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, मैं ट्रैक्टरों की बिक्री को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संभावित सुधार के उत्साहजनक संकेत के तौर पर देखता हूं।

बजाज की वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 38 फीसदी घटकर 21,871 वाहन रह गई, वहीं निर्यात 24 फीसदी घटकर 22,820 रह गया। कुल वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 31 फीसदी घटकर इस अवधि में 44,691 वाहन रही, जो पहले 65,104 रही थी।

आयशर ट्रकों व बसों की बिक्री फरवरी में एक साल पहले के 5,337 वाहनों के मुकाबले घटकर 3,875 रह गई। निर्यात 39.4 फीसदी घट गया। उधर, वोल्वो ट्रकों की बिक्री 8 फीसदी घटकर 147 रह गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 160 रही थी।

परिदृश्य

वाघ ने कहा, बीएस-6 की ओर बढ़ने के लिहाज से हम पटरी पर हैं और बीएस-4 स्टॉक की निकासी योजना के मुताबिक हो रही है और बीएस-6 वाहनों का उत्पादन हो रहा है। चीन में कोरोनावायरस के प्रसार से आपूर्ति में अवरोध के कारण बीएस-6 की ओर बढ़ने में कुछ असर पड़ सकता है। उधर, अशोक लीलैंड के मुख्य परिचालन अधिकाकरी अनुज कथूरिया ने हाल में कहा था, मुझे नहीं लगता कि अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही तक सुधार होगा। मांग बहाल होने में कुछ वक्त लगेगा। हालांकि आंकड़ों का अनुमान लगाना मुश्किल होगा।

देश में लगातार घट रही दोपहिया की बिक्री की रफ्तार

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 2 मार्च

दोपहिया वाहनों की बिक्री

कंपनी	फरवरी 2020	फरवरी 2019	बदलाव (% में)
हीरो मोटोकॉर्प	480196	600616	-20
बजाज ऑटो	146876	186523	-21
टीवीएस मोटर	169684	231582	-27
सुजूकी	58644	57174	2.6
कुल	855400	1075895	-21

वाहन उद्योग में जारी मंदी के साथ-साथ आगामी बीएस6 उत्सर्जन मानदंड में बदलाव और स्वामित्व लागत में वृद्धि के कारण दोपहिया वाहन बनाने वाली शीर्ष कंपनियों की बिक्री लगातार घट रही है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि उनके निर्यात में वृद्धि हुई है।

बजाज ऑटो की घरेलू बिक्री फरवरी 2020 में 21 फीसदी घटकर 1,46,876 वाहन रह गई जो एक साल पहले की समान अवधि में 1,86,523 वाहन रही थी। जबकि निर्यात 15.5 फीसदी बढ़कर 1,63,346 वाहन हो गया जो एक साल पहले की समान अवधि में 1,86,523 वाहनों का निर्यात हुआ था। टीवीएस मोटर के दोपहिया वाहनों की घरेलू बिक्री फरवरी 2020 में 27 फीसदी घटकर 1,69,684 वाहन रह गई जो फरवरी 2019 में 2,31,582 वाहन थी। हालांकि फरवरी 2020 में कंपनी के दोपहिया वाहनों का निर्यात 23 फीसदी बढ़कर 66,207 वाहन हो गया जो फरवरी 2019 में 54,029 वाहन रहा था।

टीवीएस ने कहा कि कंपनी डीलर के स्तर पर बीएस4 वाहनों का स्टॉक घटा रही है और उसे पूरी उम्मीद है इस महीने उसकी खपत हो जाएगी। जहां तक कोरोनावायरस के प्रभाव का सवाल है तो कंपनी ने कहा कि बीएस6 उत्सर्जन मानदंड वाले वाहनों के कलपुर्जे की आपूर्ति शृंखला पर उसका प्रभाव पड़ा है। हालांकि उसे जल्द से जल्द सामान्य करने की कोशिश की जा रही है।

सुजूकी मोटरसाइकिल ने फरवरी 2020 में घरेलू बाजार में 58,644 वाहनों की बिक्री की जो एक साल पहले की समान अवधि में हुई बिक्री के मुकाबले 2.6 फीसदी अधिक है। फरवरी 2019 में कंपनी ने घरेलू बाजार में 57,174 वाहनों की बिक्री की थी।

रॉयल एनफील्ड ने फरवरी 2020 में बिक्री में 1.4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की। महीने के दौरान कंपनी ने 63,536 वाहनों की बिक्री की जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 62,630 वाहनों का रहा था। निर्यात में गिरावट के बावजूद कंपनी ने बिक्री में वृद्धि दर्ज की है। महीने के दौरान 350 सीसी इंजन वाले मॉडलों की बिक्री 57,292 वाहनों पर लगभग स्थिर रही जबकि 350 सीसी से ऊपर के मॉडलों की बिक्री में 11.5 फीसदी की वृद्धि हुई। कंपनी के खुलासों के अनुसार, फरवरी 2020 में कंपनी के दोपहिया वाहनों का निर्यात करीब 8 फीसदी घटकर 2,348 वाहन रह गई जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 2,564 वाहन रहा था।

एसबीआई कार्ड्स के आईपीओ में एफपीआई की भागीदारी पर असर

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 2 मार्च

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का एक वर्ग एसबीआई कार्ड्स ऐंड पेमेंट सर्विसेज के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम में कई आवेदन शायद नहीं कर पाएगा। देसी बाजार की चौथी सबसे बड़ी पेशकश में संस्थागत निवेशकों की काफी दिलचस्पी की संभावना है क्योंकि सार्वजनिक निर्गम लाने वाली यह पहली कार्ड कंपनी है।

एफपीआई के लिए 2019 में जारी दिशानिर्देश के मुताबिक, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स (एमआईएम) ढांचे के तहत एक पैन (अलग-अलग लाभार्थी के खाता संख्या के साथ), क्लाइंट आईडी और डिपॉजिटरी आईडी के जरिये जमा कराई गई बोली को अलग-अलग बोली शायद नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि सभी एक पैन व अलग-अलग डीमैट खाते वाले सभी गैर-एमआईएम निवेशकों को एक निवेशक माना जाएगा और वह आईपीओ में कई बोली लगाने में सक्षम नहीं होगा।

मौजूदा नियमों के तहत सामान्य तौर पर किसी आईपीओ में एक पैन कार्ड के जरिए कई आवेदन करने वालों का आवेदन खारिज हो जाता है। हालांकि पहले के नियमों में म्युचुअल फंडों और विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए अपवाद का प्रावधान किया गया था।

साल 2003 में जारी सेबी के सामान्य सूचना दस्तावेज में कहा गया था, एक पैन कार्ड पर अलग-अलग लाभार्थी के खाते, क्लाइंट आईडी व डीपी आईडी के साथ म्युचुअल फंडों और एफपीआई के खातों के जरिये जमा कराई बोली को मल्टीपल बिड नहीं माना जाएगा।

मौजूदा सूचना दस्तावेज में हालांकि सिर्फ एफपीआई को एमआईएम ढांचे के तहत कई आवेदन जमा कराने की अनुमति है।

एक कस्टोडियन ने कहा, सेबी को देखना चाहिए कि मौजूदा एफपीआई की व्यवस्था में एक पैन व अलग-अलग डीमैट खाते के साथ एमआईएम के अलावा कुछ वैध ढांचे हैं। उन्हें कई आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए।

नए दिशानिर्देश से अम्ब्रेला फंड पर असर पड़ सकता है, जिसका एफपीआई पंजीकरण एकसमान है। अम्ब्रेला फंड सामूहिक निवेश योजना है, जिसका अस्तित्व एक कानूनी इकाई के तौर पर होता है, लेकिन इसके अलग-अलग उप-फंड होते हैं, लिहाजा वैयक्तिक निवेश फंडों के तौर पर इनकी ट्रेडिंग होती है।

एसआईसीएवी फंडों के साथ यूरोप में यह सामान्य है, जो ओपन ऐंडेड म्युचुअल फंडों के समान है।

भारत में निवेश करने वाले करीब 20 फीसदी एसआईसीएवी फंडों का एफपीआई पंजीकरण एकसमान हो सकता है और विशेषज्ञों का कहना है कि इस पर असर पड़ सकता है।

साल 2019 में जारी एफपीआई के दिशानिर्देशों में प्रोप्राइटरी डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट व एफपीआई के ओडीआई निवेश गतिविधियों के लिए अलग-अलग पंजीकरण की बात कही गई है।

ऐसे में पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी करने वाले एफपीआई उसी पंजीकरण के तहत डेरिवेटिव में निवेश नहीं कर सकते।

पूंजी जुटाने की योजना पर विचार करेगा पीएनबी हाउसिंग का बोर्ड : पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक 3 मार्च को होगी, जिसमें करीब 1,500-1,600 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाने की योजना पर विचार किया जाएगा ताकि कारोबारी बढ़त को सहारा दिया जा सके। कंपनी ने पात्र संस्थागत नियोजन या तरजीही शेयरों के जरिए रकम जुटाने का विकल्प खुला रखा है।

कंपनी को उम्मीद है कि उसकी परिसंपत्तियां मार्च 2023 तक करीब 15 से 18 फीसदी सालाना चक्रवृद्धि की रफ्तार से बढ़ेगी। *बीएस*

विनिर्माण गतिविधियों में थोड़ी नरमी

फरवरी में पीएमआई 54.5 रहा, यह जनवरी में 55.3 के मुकाबले है मामूली कम

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 2 मार्च

फरवरी में लगातार दूसरे महीने विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत वृद्धि बरकरार रही। हालांकि दुनिया भर में तेजी से फैलते कोरोनावायरस के कारण परिदृश्य कमजोर बना हुआ है।

निक्केई भारत विनिर्माण परचेज मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) फरवरी में 54.5 पर रहा, जो जनवरी में आठ साल के सर्वोच्च स्तर 55.3 पर था। पीएमआई की गणना 50 अंक से ऊपर रहना क्षेत्र में विस्तार को बताता है जबकि 50 से नीचे रहना गिरावट को दर्शाता है। पिछले साल अक्टूबर में पीएमआई दो साल के निचले स्तर 50.6 पर आ गया था। हालांकि उसके बाद मुश्किल दौर से गुजर रहा यह क्षेत्र धीरे-धीरे लगातार मजबूत हो रहा है।

हालांकि आधिकारिक आंकड़े बहुत उत्साहजनक नजर नहीं आ रहे हैं। ये दर्शाते हैं कि दिसंबर तक विनिर्माण क्षेत्र में कमजोरी बनी रही। देश का कुल औद्योगिक उत्पादन दिसंबर में 0.3 फीसदी घटा था। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था के आठ प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन को मामूली सुधार का संकेत बताया है। कोर क्षेत्र की वृद्धि जनवरी में लगातार दूसरे महीने 2.2 फीसदी बढ़ी है, जबकि इससे पहले चार महीनों में गिरावट दर्ज की गई थी।

विनिर्माण क्षेत्र में आ रहा धीरे-धीरे सुधार

- कुल बिक्री बढ़ोतरी में निर्यात की अहम भूमिका रही
- विनिर्माण क्षेत्र की हालत सुधरने के बावजूद कोरोनावायरस के चलते क्षेत्र में नई नियुक्तियां टलीं
- पीएमआई का 50 अंक से ऊपर रहना क्षेत्र में विस्तार को बताता है

फरवरी में विनिर्माण उत्पादन जनवरी में 91 महीनों के सर्वोच्च स्तर की रफ्तार से ही बढ़ा है। कंपनियों की प्रतिक्रिया नया कारोबार मिलने और अनुकूल बाजार स्थितियों को लेकर सकारात्मक रही है। उप-क्षेत्र के स्तर पर देखें तो वृद्धि की अगुआई उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माताओं ने की है। उनके बाद मध्यवर्ती उत्पाद विनिर्माताओं की भूमिका रही है। विनिर्माताओं के पास तेजी से ऑर्डर बढ़ रहे हैं। बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज करने वाली कंपनियों ने कहा कि यह सफल विपणन अभियानों, मजबूत मांग और अनुकूल आर्थिक स्थितियों की बदौलत संभव हुआ है।

नकदी की किल्लत से जूझ रहे इस क्षेत्र में ताजा आंकड़ों से रौनक आएगी। इनमें कहा गया है कि 2019 से इतर फरवरी के आंकड़े दर्शाते हैं कि कुल बिक्री बढ़ोतरी में निर्यात की अहम भूमिका रही है। भारतीय कंपनियों ने नवंबर 2018 से अपने माल की अंतरराष्ट्रीय मांग में दूसरा सबसे मजबूत सुधार दर्ज किया है।

सर्वेक्षण में कहा गया कि 2019 के अंत में विनिर्माताओं ने निर्यात पर जोर दिया ताकि वे कमजोर घरेलू मांग की स्थिति में खुद का वजूद बचा सकें। विदेशी ऑर्डरों में लगातार 24वें महीने बढ़ोतरी हुई। विनिर्माण क्षेत्र की हालत सुधरने के बावजूद कोरोनावायरस के चलते क्षेत्र में नई नियुक्तियां टाली जा रही हैं। नौकरियों में हाल में बढ़ोतरी तीन महीनों में सबसे कमजोर है। इस सर्वेक्षण में नवंबर में भारी तादाद में कंपनियों द्वारा छंटनी किए जाने की बात कही गई थी। लेकिन कंपनियां लगातार कच्चे माल की खरीदारी कर रही हैं क्योंकि बिक्री में अच्छी वृद्धि और ज्यादा उत्पादन की जरूरत लगातार बनी हुई है।

विनिर्माण क्षेत्र की औसत लागत में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन महंगाई सामान्य रही और यह ऐतिहासिक मानकों के हिसाब से नगण्य थी। रसायन, खाद्य, धातु, कागज, प्लास्टिक और कपड़ों जैसे कच्चे माल लगातार महंगे हो रहे हैं क्योंकि चीन में फैक्टरियां बंद हैं। चीन से ही इन कच्चे माल का ज्यादातर आयात होता था। हालांकि घरेलू मांग में सुधार को लेकर असमंजस होने से कारोबारी रुझान पर दबाव बना हुआ है। आईएचएस मार्किट में मुख्य अर्थशास्त्री पोल्लयान्ना डी लीमा ने कहा, 'भारतीय वस्तु उत्पादकों के लिए भी खतरे की घंटी बज रही है क्योंकि कोरोनावायरस फैलने से निर्यात और आपूर्ति शृंखलाओं को लेकर जोखिम बना हुआ है। उद्यमों का एक साल बाद के उत्पादन को लेकर भरोसा डगमगा रहा है, जिससे नियुक्तियां टाली जा रही हैं।' विनिर्माताओं की आशावादिता पहले ही जनवरी में तीन साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है क्योंकि कंपनियां बाजार के कमजोर हालात से डरी हुई हैं।

मनोरंजन बाजार में क्षेत्रीय चैनलों की बयार

पृष्ठ 1 का शेष

इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा तेलुगू, मलयालम, मराठी और बांग्ला सहित अन्य भाषाओं के दर्शकों से आता है। टीवी के कुल दर्शकों की संख्या में क्षेत्रीय भाषाओं का हिस्सा 2015 में 36 फीसदी था जो पिछले साल बढ़कर 40 फीसदी हो गया। इस दौरान हिंदी दर्शकों की संख्या 42.2 फीसदी से घटकर 34 फीसदी रह गई है।स्टार, ज़ी और वायकॉम18 के आधे या उससे अधिक दर्शक क्षेत्रीय भाषाओं के हैं। एक दशक पहले यह संख्या 20 से 25 फीसदी थी। ज़ी 1990 के दशक से क्षेत्रीय बाजार पर जोर दे रही है। वायकॉम18 और स्टार ने 2012 में इसका रुख किया था। हालांकि इस बार मामला दो मायनों में अलग है। पहला यह सस्ते में चैनल शुरू करने की बात नहीं हो रही है। दर्शकों की पसंद-नापसंद का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अग्रवाल ने कहा, हिंदी की तुलना में दक्षिण के बाजार पहुंच और खपत के मामले में बेहतर स्थिति में हैं। मराठी, बांग्ला या अन्य भाषाओं में हिंदी का प्रभाव है। उदाहरण के लिए मराठी दर्शकों में 70 फीसदी खपत हिंदी में है और 30 फीसदी मराठी में। बांग्ला में 45 फीसदी खपत बंगाली में है। दक्षिण में यह मेरी भाषा और अंग्रेजी का मामला है। कर्नाटक सीमा पर यह तेलुगू/कन्नड या मराठी/कन्नड की खपत हो सकती है। वायकॉम18 के क्षेत्रीय टीवी नेटवर्क के प्रमुख रवीश कुमार ने कहा, 'मराठी में प्रोग्रामिंग में परंपरा को ज्यादा महत्त्व दिया गया है। तमिल और तेलुगू में कोई समस्या नहीं है जबकि बंगाली पहचान के लिए संघर्ष कर रही है।' प्रोग्रामिंग, विज्ञापन और लागत, हर जगह इसका असर दिखता है। उन्होंने कहा, 'पहले क्षेत्रीय बाजारों में बहुत ज्यादा एकरूपता थी। लेकिन अब 80 फीसदी प्रोग्राम खास तौर पर उसी बाजार के लिए होते हैं और केवल 20 फीसदी कार्यक्रमों का रिमेक बनाया जाता है या उन्हें डब किया जाता है।' वाज ने कहा, केबीसी और बिग बॉस जैसे बड़े कार्यक्रम क्षेत्रीय टीवी पर उपलब्ध हैं। इनमें स्थानीय सामग्री के साथ राष्ट्रीय स्तर के प्रॉडक्शन वैल्यू हैं। इस तरह दर्शकों की संख्या बढ़ी है। अग्रवाल ने कहा कि जब क्षेत्रीय चैनल हर सप्ताह 12-13 के बजाय 25 घंटे क्षेत्रीय सामग्री पेश करते हैं तो जाहिर है कि दर्शकों के देखने का समय भी दोगुना या तिगुना होता है।क्षेत्रीय चैनलों की इस दौर की वृद्धि में दूसरा अंतर भाषा की पसंद का है।

विलय के बाद बैंक की 10 हजार शाखाएं

नम्रता आचार्य
कोलकाता, 2 मार्च

इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक के विलय से बनने वाले बैंक की अगले 2-3 साल में करीब 10,000 शाखाएं होंगी और उनका संयुक्त रूप से कारोबार 10 लाख करोड़ रुपये होगा। इलाहाबाद बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही। दिसंबर, 2019 के अंत में इलाहाबाद बैंक का कुल कारोबार करीब 3.94 लाख करोड़ रुपये था, जबकि इंडियन बैंक का कारोबार करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह दोनों बैंकों का संयुक्त रूप से कारोबार करीब 8.4 लाख करोड़ रुपये है। अधिकारी ने कहा कि बैंक विलय पर सरकार की अधिसूचना का इंतजार कर रहा है और 1 अप्रैल 2020 की डेडलाइन पूरी करने के लिए तैयार है।

एनएचएआई मई में शुरू करेगा इनविट!

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 2 मार्च

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के मई में अपनी सड़क परियोजनाओं की पहली खेप को बुनियादी ढांचां निवेश न्याय (इनविट) में शामिल करने के आसार हैं। संस्थागत निवेशकों और निजी फंडों को इन परियोजनाओं में हिस्सेदारी की पेशकश की जाएगी। एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि इनविट बनाना लंबी प्रक्रिया है। इस तरह की पहली पेशकश को इस साल मई तक शुरू करने के लिए एक तारीखवार कार्ययोजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा, 'हम पहली पेशकश प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिये करेंगे। इसका प्रदर्शन देखने के बाद हम सार्वजनिक निर्गम के बारे में विचार करेंगे।'

प्रस्तावित इनविट के तहत जिन परियोजनाओं की पेशकश की जाएगी, उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। इनविट म्युचुअल फंडों जैसी एक निवेश योजना है, जिसमें व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 दिसंबर 2019 को एनएचएआई को इनविट की स्थापना की मंजूरी दी थी ताकि राजमार्ग परिसंपत्तियों से पैसा जुटाया जा सके। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जनवरी 2020 में इनविट का खाका पेश किया था, जिसके जरिये एनएचएआई शुरुआत में 15,000 से 20,000 करोड़ रुपये जुटाएगा।

एनएचएआई की इनविट केंद्र सरकार की इस तरह की पहली पेशकश होगी। सरकार के नियंत्रण वाली पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल) में कुछ परियोजनाओं को एक इनविट में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। एनएचएआई की पेशकश केंद्र सरकार की बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सरकारी खर्च को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने के वैकल्पिक स्रोतों की योजना का हिस्सा है। ऐसा करना इसलिए अहम है क्योंकि मौजूदा समय में बिल्ट, ऑपरेट ऐंड ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल में निजी निवेश घट रहा है। बीओटी मॉडल के तहत पूरी शुरुआती लागत डेवलपर वहन करता है। हालांकि बोली के समय डेवलपर सरकार को सब्सिडी देने के लिए कहा सकता है।

इनविट पेशकश के अलावा सरकार लंबी अवधि की परियोजनाओं की खातिर धन जुटाने के लिए घरेलू ऋणदाताओं से करार कर रही है। इसके लिए केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ मिलकर काम कर रहा है। इनविट में निवेशकों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के लिए नियमित प्रतिफल मिलता है। निजी क्षेत्र की दो सड़क डेवलपरों- आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर और एमईपी इन्फ्रा ने धन जुटाने के लिए इनविट का रास्ता अपनाया है।

नई पहल

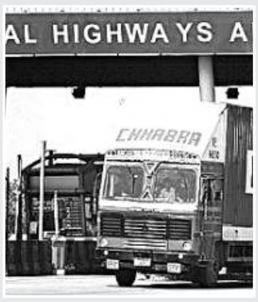

- एनएचएआई अपनी सड़क परियोजनाओं की पहली खेप इनविट में शामिल करेगा
- संस्थागत निवेशकों व निजी फंडों को परियोजनाओं की हिस्सेदारी की पेशकश होगी
- एनएचएआई शुरुआत में 15,000 से 20,000 करोड़ रुपये जुटाएगा

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 14

जीएसटी न बढ़ाएं

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह लगातार चौथे महीने एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया। सरकार ने फरवरी में 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाए जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 8.3 फीसदी अधिक है। हालांकि यह राशि उससे पिछले महीने संग्रहीत 1.1 लाख करोड़ रुपये से कुछ कम थी। जीएसटी संग्रह के एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के स्तर पर स्थिर होने की बात उत्साहजनक है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च संग्रह की एक वजह इनपुट क्रेडिट न देना भी हो सकती है। ऐसे में यह देखना अहम है कि आने वाले महीनों में यह रुझान बरकरार रहता है या नहीं। खासतौर पर वित्त वर्ष के अंत के बाद।

सुधार के बावजूद संग्रह में वृद्धि पहले जताए गए अनुमानों से काफी कम है। परिणामस्वरूप राज्यों को होने वाली कमी की भरपाई की आवश्यकता पड़ रही है और यह केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच विवाद का विषय बन सकता है।

केंद्र सरकार का कहना है कि कानून के मुताबिक राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति केवल क्षतिपूर्ति फंड से ही दी जा सकती है।

हाल ही में अंग्रेजी समाचार पत्र 'द इंडियन एक्सप्रेस' के साथ बातचीत में केंद्रीय राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने कहा, 'यदि कमी, क्षतिपूर्ति फंड द्वारा दी जाने वाली राशि से ज्यादा है, तो जीएसटी परिषद को यह देखना होगा कि वह क्षतिपूर्ति उपकर या दरें बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर सकती है?' जैसा कि इस समाचार पत्र ने हाल ही में लिखा, विभिन्न वर्षों का अधिशेष इस्तेमाल करने के बावजूद चालू वर्ष में क्षतिपूर्ति में करीब 28,000 करोड़ रुपये की राशि कम पड़ी।

चूंकि क्षतिपूर्ति उपकर का संग्रह पर्याप्त नहीं है इसलिए जीएसटी परिषद उपकर या दरों में इजाफा करने पर विचार कर सकती है। उसके लिए बेहतर यही होगा कि वह फिलहाल दरों में इजाफा न करे।

आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि कमजोर बनी हुई है और जीएसटी दरों में इजाफा या उपकर में बढ़ोतरी से मांग और कमजोर होगी और सुधार की संभावना कमजोर होगी। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 4.7 फीसदी की दर से बढ़ी। जबकि पिछली तिमाही का संशोधित अनुमान 5.1 फीसदी था।

इसके अलावा यह समझना भी आवश्यक है कि जीएसटी संग्रह में 14 फीसदी वृद्धि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति देना शुरू से ही हकीकत से दूर था।

ऐसे में परिषद यदि हर्जाने का नए सिरे से आकलन करे तो बेहतर होगा। इस बात की संभावना बहुत कम है कि ऐसे वक्त में खपत व्यय 14 फीसदी की दर से बढ़ेगा जबकि महंगाई समायोजित किए बगैर भी अर्थव्यवस्था के केवल 7.5 फीसदी की दर से बढ़ने की बात कही जा रही है। इसके अलावा तमाम अन्य मौकों की तरह परिषद को दरों में कमी भी नहीं करनी चाहिए। कम से कम तब तक कि जब तक राजस्व और व्यवस्था स्थिर नहीं हो जाती।

काफी संभव है कि राज्य कम क्षतिपूर्ति स्वीकार न करें क्योंकि इसका असर उनके बजट पर पड़ेगा।

आर्थिक मंदी ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी तथा अन्य अप्रत्यक्ष कर संग्रह को भी प्रभावित किया है। परंतु इस मोड़ पर कर दरों में इजाफा करने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा।

इसके बजाय परिषद को जीएसटी तंत्र की खामियां दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इससे राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्षतिपूर्ति को हकीकत के करीब लाने से भी राज्यों को यह प्रोत्साहन मिलेगा कि वे राजस्व जुटा सकें। इस बीच राज्यों के बजट को भी नई आर्थिक वास्तविकता के अनुरूप करना होगा।

अजय मोहंती

सही काम के लिए सही व्यक्ति का हो चयन

वरिष्ठ सरकारी पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति से नीति-निर्माण स्तर पर उच्च गुणवत्ता लाने में मदद मिल सकती है। इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया में सुधारों की जरूरत बता रहे हैं **जैमिनी भगवती**

भारत की आर्थिक प्रगति में जारी सुस्ती की वजह से लोगों के लिए नए मौके पैदा करने और नौकरियों के सृजन में भारी कमी आई है। इसके अलावा पिछले कई साल से वस्तुओं के व्यापार में आ रही गिरावट प्रतिस्पर्द्धा-भाव में पतन को दर्शाती है। परेशान करने वाले इन रुझानों के कारणों एवं परिणामों पर सार्वजनिक चर्चा गत 1 फरवरी को बजट पेश होने के पहले और बाद में भी हुई है।

निजी बातचीत में लोग अक्सर यह चिंता जाहिर करते हैं कि निर्णय निर्माण से जुड़े तमाम वरिष्ठ नियामकों एवं अधिकारियों के पास ठोस शख्सियत, प्रासंगिक कार्य-अनुभव या उससे जुड़ी जटिलताओं की समझ नहीं है। यह संभव है कि महत्त्वपूर्ण पदों पर बैठे कुछ लोगों ने चुप्पी साध ली और बेहतर समझ रखते हुए भी बोलने के लिए खड़े नहीं हुए। या फिर 1970 के दशक के मध्य में आपातकाल के दौरान सरकार में वरिष्ठ पदों पर आसीन कई लोगों के बारे में जैसा कहा जाता है, इन लोगों से भी जब झुकने को कहा गया तो वे रेंगकर चलने से भी अधिक के लिए राजी हो गए।

नई दिल्ली में बैठी सरकार पर नजर रखने वाला कोई भी व्यक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) से परिचित होगा। एसीसी से अनजान लोगों के लिए बता दूं कि इस मंत्रिमंडलीय समिति के अगुआ प्रधानमंत्री होते हैं और गृह मंत्री एवं संबंधित मंत्रालय के मंत्री इसके दो अन्य सदस्य होते हैं। सभी संवैधानिक पदों, नियामकीय संस्थाओं के प्रमुखों, केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पदों के लिए एसीसी ही नियुक्तियों को मंजूरी देती है और उस नियुक्ति का कार्यकाल भी तय करती है। मसलन, चुनाव आयुक्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई), प्रतिस्पर्द्धा आयोग एवं केंद्रीय विद्युत नियामकीय आयोग के प्रमुखों, सूचना आयुक्तों, केंद्र सरकार के सचिवों, आरबीआई गवर्नर, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण और पेंशन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण और वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार जैसे पदों पर नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ही करती है।

फिलहाल संवैधानिक, नियामकीय एवं केंद्र में सचिव स्तर के लगभग सारे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त या जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी तैनात हैं। सैद्धांतिक तौर पर यह संभव है कि इन बेहद अहम पदों पर उपयुक्त लोगों को ही नियुक्त किया गया है। हालांकि यह भी मुमकिन है कि केवल एक सेवा के ही अधिकतर सेवानिवृत्त अफसरों को ही इन वरिष्ठ पदों पर नियुक्त करने से राष्ट्रीय हित पूरा नहीं होता है। केंद्र एवं राज्य सरकारें अक्सर कम योग्य शख्स का ही चयन करती हैं लिहाजा ऐसा लगता है कि नियुक्ति की मौजूदा परंपराएं भारतीय राजनीतिक कार्यपालिका के हितों को पूरा करती है।

वित्त मंत्रालय के सीमित संदर्भ में मुझे इस समाचारपत्र के एक संपादक के साथ हुई बातचीत याद है। संपादक का यह मानना था कि मुख्य आर्थिक सलाहकार या आरबीआई गवर्नर जैसे पदों पर सरकार को यह चाहिए कि जरूरी होने पर देश के बाहर से भी बेहतरीन प्रतिभा वाले लोगों की तरफ देखे। सरकार ने कुछ मौकों पर ऐसा किया भी है और विदेश से नियुक्त किए गए लोग इसके लिए पूरी तरह योग्य थे। हालांकि मैं इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हूं कि इन लोगों को अपने कार्यशील जीवन वाले देश की सरकार या नियामकों में काम करने का कोई अनुभव था या नहीं। वैसे उनके लिए यह कोई प्रतिकूल बात नहीं थी क्योंकि वे जल्द सीख सकते हैं। हालांकि आर्थिक सलाहकार या आरबीआई गवर्नर जैसे अधिकारियों को भारत में सरकार के भीतर रहते हुए आगे बढ़ने का मौका भी होता है।

कभी-कभी यह दलील दी जाती है कि भारत के भीतर इस काम को करने के लिए एक भी सुयोग्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। सरकार से जुड़े अधिकांश पदों के लिए यह बात तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हो सकती है। इस बात की संभावना है कि विश्वविद्यालयों, विशेषज्ञता वाले संस्थानों और निजी कंपनियां अपने प्रोफेसरों, विशेषज्ञों एवं कार्यकारियों को सरकार या किसी नियामकीय संस्था में पांच साल तक काम करने के लिए मुक्त कर दें। ऐसे लोग वापस अपने संस्थान में लौटने के बाद उनके लिए एक परिसंपत्ति होंगे।

शासकीय कामकाज के बारे में जानकारी उस समय खो जाती है जब विदेश से बुलाए गए विशेषज्ञ अपने देश लौट जाते हैं। हालांकि विदेशी इंजीनियरों एवं वैज्ञानिकों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य होने पर एक तय अवधि वाली नियुक्ति के लिए रियायतें दी जानी चाहिए ताकि रेलवे, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन या डीआरडीओ जैसे संस्थानों में उनकी सेवाएं ली जा सकें।

केंद्र सरकार चयन प्रक्रिया को समय पर शुरू करने के लिए आम तौर पर अधिक सक्रियता नहीं दिखाती है। किसी पदस्थ अधिकारी का कार्यकाल पूरा होने वाला होता है लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि उसे सेवा-विस्तार मिलेगा या नहीं। वरिष्ठ पदों पर चयन प्रक्रिया पद रिक्त होने के छह महीने पहले ही शुरू हो जानी चाहिए। यह काम किसी अपवाद के बगैर होना चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं एवं समुचित कार्य-अनुभव का उल्लेख होना चाहिए। मसलन, वित्तीय क्षेत्र के पदों पर काम करने की इच्छा रखने वालों के पास किसी प्रतिष्ठित संस्थान से अर्थशास्त्र या वित्त में न्यूनतम एक डिग्री जरूर होनी चाहिए। उसके बाद पांच सदस्यीय चयन समिति को संबंधित क्षेत्र का अनुभव रखने वाले तीन उम्मीदवार छांटे जाने चाहिए। चयन समितियों में विभिन्न सेवाओं से दो सेवानिवृत्त सचिव और तीन विषय विशेषज्ञों को जगह देनी चाहिए। इनमें से एक विशेषज्ञ के पास बड़ी निजी कंपनियों में न्यूनतम 30 साल का कार्य-अनुभव होना चाहिए। पांच सदस्यों की इस समिति को उस पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए तीन उम्मीदवारों के नाम मंत्रिमंडलीय समिति के पास भेजने चाहिए।

अतीत में आजमाए जा चुके विकल्पों से बड़ा अंतर होगा अगर किसी भी उम्मीदवार के उपयुक्त पाए जाने पर एसीसी खुद अपने स्तर पर ही नाम रखने के बजाय चयन समिति से दोबारा बैठकर तीन नए नाम भेजने को कहे। ऐसा होने पर किसी को भी चुनने को लेकर एसीसी के लचीलेपन में निश्चित तौर पर कमी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस सुझाई गई प्रक्रिया से कमतर लोगों का चयन हो जाए जबकि मौजूदा परंपरा यही है कि सभी वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियां राजनीतिक कार्यपालिका के व्यक्तिनिष्ठ निर्णय पर छोड़ दी जाती है।

मैं उन लोगों से सहमति जताऊंगा जो कहते हैं कि सुझाई गई यह प्रक्रिया पिछले प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझावों जैसी ही है। निश्चित तौर पर एक उदासीन रवैये का यही मतलब होगा कि हम अहम पदों पर नियुक्ति के बारे में मौजूदा नीतियों को ही जारी रखे हैं। राजनीतिक कार्यकारी उसी संदेश को सुनते हैं जो उच्च स्वर में बोला जाए। उनके लिए मतदाताओं की अहमियत है और अगर एक बड़े तबके की यह राय बन जाती है तो भारत की सरकारें अपने लिए लाभकारी नीतियों को भी बदल देती हैं।

(लेखक पूर्व राजदूत और विश्व बैंक के पूर्व अधिकारी हैं)

आंकड़ों की हकीकत और सचिवों की जवाबदेही

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

सन 2014 में जब नरेंद्र मोदी केंद्र में सत्ता में आए तब माना जा रहा था कि विभिन्न मंत्रालयों में शीर्ष अफसरशाहों के काम करने के तरीके और मंत्रालयों के कामकाज में परिवर्तन आएगा। मोदी की कार्यशैली पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अलग थी। मोदी को सिंह की तुलना में अधिकारियों से अधिक अपेक्षा करने वाला भी माना जाता था।

ऐसे में यह सवाल उठता है कि बीते कुछ वर्षों में यानी जब से मोदी ने कमान संभाली है, तब से प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के लिए क्या कुछ बदला है? एक बदलाव जिसे आसानी से देखा जा सकता है उसका संबंध प्रधानमंत्री की उस महत्त्वपूर्ण भूमिका और प्रभाव से है जो वह विभिन्न महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों में सचिवों की नियुक्ति में रखते हैं। यही कारण है कि कई प्रमुख मंत्रालयों का नेतृत्व ऐसे सचिवों के हाथ में है जिन्हें या तो मोदी ने स्वयं चुना है जिनके साथ उनकी बहुत अच्छी समझ है। कुछ मामलों में इन अधिकारियों से उनका पुराना कामकाजी रिश्ता रहा है।

यह प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों में सचिवों की नियुक्ति के मनमोहन सिंह के तरीके से एकदम अलग था। इस संबंध में अंतिम मंजूरी भले ही सिंह की ओर से आती थी लेकिन ऐसी नियुक्तियों में मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों की बहुत अहम भूमिका होती थी। जाहिर है वित्त मंत्री के रूप में प्रणव मुखर्जी इस बात पर अंतिम निर्णय लेते थे कि वित्त सचिव कौन होगा। सिंह अपने मंत्रियों की बात मानते थे।

सचिवों की नियुक्ति के प्रबंधन के इस विरोधाभासी तरीके के स्वाभाविक परिणाम की अनदेखी करना संभव नहीं है। सिंह को जहां अक्सर अपने जरूरी कदमों का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में कठिनाई होती थी (क्योंकि संबंधित सचिव प्रधानमंत्री के बजाय अपने प्रभारी मंत्रियों से अधिक जुड़ाव रखते थे) जबकि मोदी का उन पर पूरा नियंत्रण है और माना जाता है कि वह सचिवों से सीधे संपर्क करके काम कराते हैं। इस दौरान कई बार तो प्रभारी मंत्रियों को भी उस संवाद में शामिल नहीं किया जाता।

संक्षेप में कहें तो मोदी के अधीन प्रधानमंत्री कार्यालय अधिक ताकतवर हो गया है और मंत्रियों के पास यह मानने की वजह है कि उनके सचिवों की वफादारी केवल उनके प्रति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय और खासतौर पर प्रधानमंत्री के प्रति भी है। यह धारणा उस समय और मजबूत हो गई जब मोदी ने सचिवों के छोटे और बड़े समूहों से उनके कामकाज के बारे में चर्चा की। इस बैठक में वे सारे मंत्री मौजूद भी नहीं थे जिनके साथ ये सारे सचिव काम करते थे।

क्या इस बदलते समीकरण ने मोदी के मंत्रियों के कामकाज और उनके प्रभाव पर असर डाला है? इस बारे में साफ कुछ नहीं कहा जा सकता और न ही स्पष्ट तौर पर कोई यह दावा कर सकता है कि अपने मंत्रालयों में सचिवों की नियुक्ति में मंत्रियों की घटती भूमिका के कारण सचिवों पर मंत्रियों के प्रभाव में कमी आई है। परंतु एक सवाल अक्सर उठा है कि कैसे सचिवों के जवाबदेही के सिद्धांत पर असर पड़ा है।

इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय का हालिया घटनाक्रम भी ध्यान देने लायक है। वर्ष 2020-21 का आम बजट गत 1 फरवरी को पेश किया गया। राजस्व अनुमान तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल वित्त मंत्रालय के सचिव अक्सर प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ सलाह-मशविरा करते रहते हैं। उनके पास कम से कम 15 जनवरी तक के कर संग्रह रुझानों की पहुंच होनी चाहिए। महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी आंकड़े दर्शाते हैं कि दिसंबर के अंत में केंद्र का कुल कर संग्रह 9.05 लाख करोड़ रुपये अनुमानित था जबकि जनवरी के अंत में यह 9.98 लाख करोड़ रुपये अनुमानित था। इसके बावजूद आम बजट में 2019-20 के पूरे वर्ष के लिए 15.04 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध कर राजस्व संग्रह अनुमान प्रस्तुत किया।

यदि कर संग्रह अनुमान हकीकत से दूर रहता है तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या वित्त मंत्रालय के सचिवों को हकीकत के करीब राजस्व आंकड़े पेश करते समय अधिक चौकन्ना और सावधान नहीं रहना चाहिए? यदि वर्ष 2019-20 का वास्तविक कर संग्रह संशोधित अनुमान से भी कमतर निकलता है तो यह लगातार दूसरा वर्ष होगा जब ऐसा बड़ा विचलन देखने को मिलेगा। आखिर सचिवों की जवाबदेही का क्या? याद रहे कि गत वर्ष ऐसे ही अतिशय अनुमान लगाने में शामिल सचिवों में से एक इस वर्ष राजस्व अनुमान हासिल करने की व्यवहार्यता पर उठे सवालों की आलोचना कर रहे हैं।

इसी प्रकार विनिवेश और सब्सिडी के आंकड़ों को लेकर भी संदेह उत्पन्न हो गया है। वर्ष 2019-20 में विनिवेश प्रक्रिया से 1.05 लाख करोड़ रुपये हासिल होने का अनुमान था। संशोधित अनुमान में इन्हें घटाकर 65,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। फरवरी 2020 के अंत तक सरकार विनिवेश से केवल 33,000 करोड़ रुपये जुटा पाई। वर्ष 2019-20 की प्रमुख सब्सिडी की बात करें तो बजट में उल्लिखित 3 लाख करोड़ रुपये के अनुमान को संशोधित करके 2.27 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया।

परंतु महालेखा नियंत्रक के प्रारंभिक आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार जनवरी के अंत तक ही 2.63 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। ऐसे में कर संग्रह में और कमी के अलावा क्या 2019-20 के विनिवेश के आंकड़ों में ज्यादा बड़ी कमी देखने को मिल सकती है और क्या सब्सिडी व्यय संशोधित अनुमान से परे जा सकती है? और क्या प्रधानमंत्री कार्यालय जो बजट की तैयारी में वित्त मंत्रालय के अफसरशाहों के साथ लगा हुआ था, उसे पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए ताकि ये आंकड़े हकीकत के करीब दिख सकें? बजट में हकीकत के करीब आंकड़े पेश करना अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

कानाफूसी

गांव में रुकें पर्यटक

मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण पर्यटन नेटवर्क विकसित करने जा रही है। वह इसका ऑनलाइन प्रचार भी करेगी। पर्यटन विभाग ने इस उद्देश्य के लिए 60 गांवों का चयन किया है। ये गांव प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों सांची, ओरछा और खजुराहो आदि के करीब स्थित हैं। प्रदेश का पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग स्वयं सहायता समूहों की मदद से इन गांवों में होम स्टे विकसित करेगा जहां पर्यटक रुक सकेंगे। राज्य सरकार इस काम में मनरेगा के फंड का भी इस्तेमाल करेगी। मध्य प्रदेश पर्यटन के प्रबंध निदेशक फैज अहमद किदवई कह चुके हैं कि इस योजना को सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। ऐसे कुछ केंद्र ओरछा के निकट शुरू किए गए हैं। राज्य सरकार उन्हें मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया से उत्साहित है।

महंगा पड़ा राय मांगना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे कर चुकी है। इस अवसर पर राज्य सरकार ने एक पुस्तिका प्रकाशित करने की योजना बनाई है ताकि सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया जा सके। सरकार ने इस पुस्तिका का शीर्षक सुझाने के लिए सोशल मीडिया पर आह्वान किया जो शायद उपयुक्त नहीं रहा। एक व्यक्ति ने इसके लिए 'तीन साल बेमिसाल' शीर्षक सुझाया तो एक अन्य ने कहा कि इसे 'तीन साल: यूपी बेहाल' का नाम दिया जाना चाहिए। एक व्यक्ति ने तो यह तक कह डाला कि पुस्तक का नाम होना चाहिए 'उत्तर प्रदेश बना हत्या प्रदेश।' सोचने वाली बात यह है कि जब प्रदेश सरकार के पास जन संपर्क विभाग है और उसका सोशल मीडिया संभालने के लिए कुछ निजी एजेंसियां हैं तो भला आम जनता से राय मांगने की क्या जरूरत?

आपका पक्ष

निर्यात का महत्त्व समझें युवा

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी हिस्सेदारी वहां से होने वाले निर्यात की होती है। जब देश की घरेलू मांग कम हो या मंदी से प्रभावित हो, उस स्थिति में दुनिया के अन्य बाजारों में हमें अपने उत्पाद का निर्यात करने का अवसर होता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और दुनिया के अनेक देशों में अपने उत्पाद पहुंचाने में लगा है। वह अपने निर्यात के दम पर आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की राह पर है। किसी जमाने में भारत की निर्यात हिस्सेदारी ज्यादा हुआ करती थी, उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अब देश का निर्यात सीमित रह गया है। अब समय आ गया है, युवा भारत के लोग इसमें अपनी भागीदारी बढ़ाएं। सरकार को निर्यात को लेकर एक विशेष कार्यक्रम शुरू करना चाहिए जिसके जरिये देश के युवाओं को इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके।

विमलेंद्र मणि त्रिपाठी, गोरखपुर

सरकार को निर्यात को लेकर एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना चाहिए

अपराधियों से मुक्त हो राजनीति

राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण अब कोई नई बात नहीं रह गई है बल्कि यह एक सामान्य बात बनती जा रही है। एक समय था जब राजनीति को पवित्र और सेवा का क्षेत्र समझा जाता था। लेकिन आज की परिस्थिति इसके उलट होती जा रही है। सैकड़ों वर्षों के बाद हमें अंग्रेजी दासत्व से मुक्ति मिली थी। तब नेताओं ने गांधी जी के 'रामराज्य' के स्वप्न को साकार करने का संकल्प किया था। लेकिन आज राजनीति का अपराधीकरण जिस कदर बढ़ रहा है उसे देखते हुए कोई भी कह सकता है कि हम अपने लक्ष्य से पूरी तरह से भटक चुके हैं। ऐसी स्थिति में राजनीति में अपराधियों के बढ़ते वर्चस्व के कारणों की पहचान कर तुरंत उसका समाधान करना नितांत जरूरी हो चुका है। इस दिशा में सोचने पर सर्वप्रथम हम पाते हैं कि देश की चुनाव प्रक्रिया में भी आमूलचूल बदलाव लाने की आवश्यकता है। हमारे यहां राजनीति में धनबल और बाहुबल का बोलबाला है। एक आकलन के अनुसार सामान्यत: 90 प्रतिशत से भी अधिक नेतागण या तो अत्यधिक धनाढ्य परिवारों से होते हैं अथवा उनका संबंध अपराधी तत्त्वों से होता है। गुणवत्ता कभी भी हमारी चुनाव प्रक्रिया का आधार नहीं रही है। देश की लचर न्याय प्रणाली का भी इन्हें खूब लाभ मिलता है। यदि हम सही में राजनीति को अपराधियों की गिरफ्त से बचाने के प्रति गंभीर हैं तो कानून ऐसा होना चाहिए कि आपराधिक मामलों का सामना कर रहे व्यक्ति पर उसके न्यायालय से पूरी तरह से बरी हुए बिना चुनाव में भाग लेने पर भी प्रतिबंध हो। ऐसा करने पर अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कुछ हद तक अंकुश लगेगा। राजनीति में अपराधियों की बढ़ी संख्या पर यदि संसद भी रोक न लगा सके, अर्थात इस विषय पर कोई कानून न बना सके तो उन्हें राजनीति से दूर रखने के केवल दो ही रास्ते बचते हैं। एक तो यह कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से टिकट ही न दें लेकिन वर्तमान में देश की राजनीति पर नजर डाली जाए तो ऐसी संभावना कम ही है। दूसरा यह है कि देश की जनता ऐसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों का चुनाव ही न करे।

अनु मिश्रा, सीवान

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

जिंसों में सुधार, मगर आशंका बरकरार

शुरुआती कारोबार में धातु, सोने और कच्चे तेल की कीमतों में दिखा कुछ सुधार। निकल में तेजी रही, सीसा 1 प्रतिशत चढ़ा, जबकि तांबे, एल्युमीनियम और जस्ते में दर्ज हुआ कुछ कम इजाफा

राजेश भयानी
मुंबई, 2 मार्च

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोमवार के शुरुआती कारोबार में धातु, सोने और कच्चे तेल की कीमतों में कुछ सुधार देखने को मिला। निकल में तेजी रही, सीसा 1 प्रतिशत से चढ़ा, जबकि तांबा, एल्युमीनियम और जस्ता में इससे कुछ कम तेजी दर्ज की गई। शुरुआती वायदा कारोबार में कच्चा तेल 3 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर 51.3 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था, लेकिन बाद में इसने कुछ बढ़त गंवा दी। शुक्रवार की रात बिकवाली दबाव के बाद सोने और चांदी में सुधार देखा गया है। एमसीएक्स पर भी, कई जिंसें ऊंचाई के साथ कारोबार कर रही थीं।

कॉमट्रेंड्ज रिसर्च के निदेशक टी ज्ञानशेखर ने कहा, 'हालांकि यह कहना कठिन है कि बुरा दौर बीत गया है।'

उनका कहना है कि मौजूदा समय में देखा गया सुधार टिकाऊ साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि कोरोनावायरस का प्रसार बढ़ा है। इस स्थिति में अस्थायी जोखिम से ढांचागत आर्थिक समस्या पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा, 'यदि कोरोनावायरस का प्रसार चीन तक सीमित रहता तो आर्थिक सुधार की संभावना बरकरार रहती। लेकिन चूंकि यह वायरस एक देश से दूसरे देश में फैल रहा है, इसलिए इससे ढांचागत आर्थिक कमजोरी पैदा होने की आशंका है।'

वायरस का डर

- **एमसीएक्स पर भी सोमवार को कई जिंसों में ऊंचाई के साथ हुआ कारोबार**
- **लेकिन यह कहना कठिन है कि बुरा दौर बीत गया है, क्योंकि कोरोनावायरस का प्रसार बढ़ा है**
- **जानकारों का कहना है कि कई देशों ने पहली तिमाही के लिए वृद्धि के अनुमान घटाए हैं**

शुक्रवार रात बिकवाली के दबाव के बाद सोने और चांदी में देखा गया सुधार, शुरुआती वायदा में कच्चा तेल 3 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा, लेकिन बाद में फिसला

चूंकि चीन में कोरोना महामारी से धातु और कच्चे तेल की कीमतों में 7-17 प्रतिशत के बीच गिरावट देखी गई है। इस्पात, लौह अयस्क भी अच्छी स्थिति में नहीं हैं। कच्चे तेल की कीमतों के बाद, रसायनों, पेट्रोरसायनों और कई कृषि जिंस (पाम तेल समेत) कीमतों पर दबाव पड़ा है।

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार शुरू होने के बाद से चीन ने राहत पैकेजों की घोषणा की है। इसका मकसद उद्योगों की सहायता करना था। जहां पहले दौर की सफल वार्ताओं के साथ व्यापारिक टकराव लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन अभी समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। रेगसस कंसल्टिंग के निदेशक संदीप डागा ने कहा, 'कोविड-19 से संबंधित मंदी एक कड़वी सच्चाई है। कई देशों ने पहली तिमाही के लिए अपनी वृद्धि के अनुमान घटाए हैं। आने वाला डेटा खराब रह सकता है।'

कई देशों द्वारा घोषित राहत पैकेजों के बारे में बताते हुए डागा ने कहा, 'इससे अगली तिमाही में अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों को राहत मिल सकती है, लेकिन हम इसे लेकर आशंकित हैं कि क्या मरीज अस्पताल से सही हालत में घर लौट सकते हैं। हमारा मानना है कि अगली दो तिमाहियों के दौरान सुधार की उम्मीद मजबूत होगी।'

लंदन स्थित निवेश बैंक नैटिक्सिस की इकाई नैटिक्सिस कमोडिटी रिसर्च ने इस वायरस के प्रसार के बाद इस साल के लिए सभी धातुओं के लिए परिदृश्य को बदलकर 'ऋणात्मक' कर दिया है। कंपनी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है, 'चीन दुनिया के एल्युमीनियम का 56 प्रतिशत उत्पादित और खपत करता है, यह दुनिया में कुल तांबे का भी 38 प्रतिशत उत्पादन करता है और 52 प्रतिशत खपत करता है।' नैटिक्सिस का यह भी कहना है कि एल्युमीनियम उत्पादन के मामले में, बॉक्साइट और कास्टिक सोडा, दोनों के लिए खरीद संबंधित समस्याएं हैं। जहां तक तांबे, सलफ्यूरिक एसिड उत्पादन का सवाल है, तो लॉजिस्टिक समस्याएं पैदा हुई हैं, क्योंकि स्मेल्टरों को इसका स्टॉक रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

निर्यात पर रोक हटने से आस

बीएस संवाददाता
मुंबई, 2 मार्च

महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज की थोक कीमतों में आई भारी गिरावट और किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने 15 मार्च से प्याज निर्यात पर लगी रोक हटाने का जो फैसला किया उससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होने की आस जगी है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के किसान अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर देंगे। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक पिछले पांच साल के दौरान राज्य के साढ़े चौदह हजार से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने प्याज निर्यात पर लगी रोक हटाने का ऐलान किया है। केंद्रीय वाणिज्य एंव उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ट्वीट करके कहा कि सरकार द्वारा किसान हित में 15 मार्च से प्याज निर्यात की अनुमति दे दी जाएगी। इस निर्णय से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। महाराष्ट्र के नाशिक में आज किसानों ने प्याज निर्यात पर लगी रोक हटाने संबंधी अधिसूचना जल्द जारी करने की मांग की।

एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में आज प्याज के थोक दाम घटकर नौ से 16.35 रुपये प्रति किलोग्राम रह गए, जबकि दैनिक आवक 10,500 क्विंटल रही। दिसंबर 2019 में मंडी में इसके थोक दाम 20 से 84.01 रुपये प्रति किलोग्राम थे। पुणे मंडी में आज प्याज के दाम घटकर पांच से 17 रुपये प्रति किलोग्राम रह गए और मंडी में दैनिक आवक 23,957 क्विंटल रही। राज्य की मनमाड मंडी में प्याज का भाव घटकर पांच से 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। प्याज किसानों ने नीलामी नहीं होने दी और सड़क पर इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया।

हाल ही में केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट करके निर्यात पर लगी रोक हटाने की जानकारी दी थी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पिछले सप्ताह मंत्रियों के समूह की बैठक में प्याज निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया था। इस बारे में पासवान ने ट्वीट करते हुए कहा था कि चूंकि प्याज की कीमत स्थिर हो गई है और प्याज की भारी पैदावार हुई है, इसलिए सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। हालांकि इस बारे में अब तक विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की गई है जिससे प्याज के किसान नाराज हैं।

गौरतलब है कि सरकार ने सितंबर 2019 में प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था और प्रति टन प्याज पर 850 डॉलर का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) घोषित किया था। उस समय मांग और आपूर्ति में अंतर होने के कारण प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी थीं। महाराष्ट्र सहित प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में अत्यधिक बारिश और बाढ़ के कारण खरीफ की फसल प्रभावित होने से प्याज उत्पादन में कमी आई थी। इस समय रबी सत्र के प्याज की आवक मंडियों में शुरू हो गई है तथा आगे चलकर दैनिक आवक और बढ़ने की संभावना है।

जगी उम्मीद

- **प्याज की थोक कीमतों में भारी गिरावट और किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र ने 15 मार्च से प्याज निर्यात पर लगी रोक हटाने का किया है फैसला**

दिल्ली हिंसा: कितना हुआ नुकसान

दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आकलन के अनुसार उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा होने से करीब 25,000 करोड़ रुपये का हुआ नुकसान, सड़क किनारे मौजूद कई शोरूम में आग लगा दी गई जबकि थोक माल से भरे गोदाम लूट लिए गए

सोमवार को दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्र शिव विहार का दौरा करते दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव

शुभायन चक्रवर्ती, शाइन जैकब और अरूप रायचौधरी

जब दुकानों को आग लगाई जा रही थी तो अशोक शर्मा को पता था कि वह अपनी दुकान को बचाने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते। शर्मा की पेंट एवं हार्डवेयर की दुकान थी। पेंट काफी ज्वलनशील होता है। जौहरी एनक्लेव मेट्रो स्टेशन की ओर से करावल नगर में प्रवेश करने पर जौहरीपुर रोड के किनारे बाजार में उनकी दुकान सबसे बड़ी थी। सामने दुकान थी और उसके पीछे गोदाम जिसे शर्मा अपने भतीजे मुकेश के साथ मिलकर चलाते थे। उनकी दुकान और गोदाम दोनों पूरी तरह आगजनी की चपेट में आ गए।

आगजनी से पूरी तरह तहस-नहस हुई दुकान में हम टूटे हुए शटर से झांक रहे थे तो शर्मा ने कहा, 'हमारी दुकान और गोदाम में कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपये मूल्य के पेंट, घरेलू इलेक्ट्रिक उपकरण और सैनिटेरी हार्डवेयर एवं फिटिंग के सामान रखे हुए थे।' पेंट के डिब्बे, बाथरूम फिटिंग, पाइप आदि सबकुछ पिघले हुए दिख रहे थे।

नगर निगम के कर्मचारी बुल्डोजर और ट्रैक्टर के जरिये सड़कों से मलबा साफ कर रहे थे। करावल नगर किसी युद्ध क्षेत्र की तरह दिख रहा है। कभी कार और मोटरसाइकिलों की भीड़भाड़ वाली उस सड़क पर ईंट, पत्थर, बोतल, कचरा, जले हुए भूसे आदि बिखड़े पड़े थे। अधिकतर मकान और दुकान जला दिए गए और उनमें से कुछ से धुआं अब भी निकल रहा था। चारों ओर मौत और निराशा का मंजर दिख रहा था। इस हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित हुए लोग प्रशासन को पूरी तरह विफल बता रहे थे।

उत्तर पूर्व दिल्ली के कारोबारी संगठन इस दंगे के कारण हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मानना है कि करीब 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है क्योंकि मुख्य सड़क के किनारे मौजूद तमाम शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया। थोक माल से भरे कई गोदामों में लूटपाट की गई और छोटी फैक्टरियों के भीतर तोड़फोड़ की गई। शर्मा ने उत्तर प्रदेश के लोनी बॉर्डर से सटे उत्तर पूर्व दिल्ली के इस क्षेत्र में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी और करीब 20 वर्ष पहले उन्होंने अपनी दुकान और गोदाम खोला था। शर्मा कहते हैं, 'यह मिलाजुला बाजार है। कोई दुकान हिंदू की है तो कोई मुसलमान की। कभी कोई समस्या नहीं हुई। यहां तक कि 1984 और 1992-93 में भी सबकुछ शांत रहा। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा।' बिजनेस स्टैंडर्ड ने करावल नगर, भजनपुरा और चांदबाग में दर्जनों दुकानदारों और गोकुलपुरी टायर बाजार एसोसिएशन (टायर बाजार में करीब 80 दुकानें जला दी गईं) के सदस्यों से बातचीत की। शर्मा उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अपने कारोबार का बीमा करा रखा था। उन्होंने कहा, 'हमारी दैनिक बिक्री आसानी से 10,000 रुपये से अधिक की हो जाती थी। अब सबकुछ खो गया। लेकिन हमें बताया गया है कि हम बीमा भुगतान के तौर पर करीब 40 लाख रुपये की उम्मीद कर सकते हैं।'

उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा के दौरान थोक माल से भरे कई गोदामों में लूटपाट की गई और छोटी फैक्टरियों में तोड़फोड़ की गई

कुछ ही मीटर दूर अमित अग्रवाल अपने थोक कारोबार को हुए नुकसान का आकलन कर रहे थे। वह उस क्षेत्र के पान एवं सिगरेट दुकानदारों को पान मसाला, गुटखा, चिप्स, स्नैक्स एवं अन्य खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति करते थे। अग्रवाल ने कहा, 'मेरे बहीखाते भी दुकान के भीतर ही थे। अब मैं नहीं जानता कि किसका मुझ पर कितना बकाया है अथवा मेरा किसी पर कितना बकाया है।'

सुर्खियों से दूर

गली के अंतिम छोड़ पर अग्रवाल के चाचा का मकान है। उनके सभी किरायेदार मुसलमान हैं। करावल नगर मिलाजुला क्षेत्र है जहां स्पष्ट तौर पर कोई हिंदू अथवा मुसलमान इलाका नहीं है। वहां हिंसा शुरू होते ही अधिकतर निवासी भाग गए थे। कुछ लोग नुकसान का आकलन करने के लिए लौटे हैं। यहां तक कि पुलिस भी हाथ में रजिस्टर लिए गश्त लगा रही है और लोगों को हुए नुकसान के बारे में पूछताछ कर रही है।

बहुत देर हो गई। लोगों की आम शिकायत है कि अन्य क्षेत्रों के विपरीत करावल नगर में सोमवार को हिंसा फैलने के करीब 36 घंटे बाद भी पुलिस अथवा मीडिया की कोई मौजूदगी नहीं दिखी। अग्रवाल के पड़ोसी गुलफाम पूर्वी दिल्ली के मंडावली में एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं। उन्होंने कहा, 'यह प्रशासन की पूरी तरह से विफलता है। बाहर कोई भी नहीं जानता कि इस क्षेत्र में आगजनी की गई।' गुलफाम दिहाड़ी पर काम करते हैं और फिलहाल उन्हें नहीं पता कि वह कब तक काम करने लायक हो जाएंगे। अग्रवाल की दुकान के बाद खाली प्लॉट में स्थानीय निवासियों के लिए पार्किंग की जगह है। वहां तमाम छोटी-बड़ी करीब 70 गाड़ियां जली पड़ी थीं। ऐसे में केवल बीमा ही पर्याप्त नहीं होगी।

भजनपुरा मार्केट एसोसिएशन के महासचिव ज्ञानपाल ने कहा, 'भारतीय जीवन बीमा निगम और न्यू इंडिया एश्योरेंस जैसी बीमा कंपनियों के दफ्तर बंद हैं और हमें लगता है कि वास्तविक नुकसान का आकलन करने वाले अधिकारियों को उत्तर पूर्व दिल्ली से आने वाले दावों पर कोई प्रतिक्रिया न देने का निर्देश दिया गया है।'

ज्ञानपाल के ही पास खड़े ताज मोहम्मद ने भी चुपचाप सिर हिला दिया। वह करीब एक सप्ताह पहले तक सिले-सिलाए कपड़ों के थोक कारोबारी थे। उन्होंने कहा, 'करीब 12 लाख रुपये के कपड़े स्वाहा हो गए जिनमें आगामी गर्मी के लिए नए कलेक्शन भी थे। पिछला साल कारोबार के लिहाज से हमारे लिए बहुत खराब रहा क्योंकि त्योहारी सीजन के दौरान कोई खरीदार नहीं था। लेकिन इस बार मुझे दमदार मुनाफे की उम्मीद थी क्योंकि चीन में कोरोनावायरस के फैलने से कपड़ों के दाम जल्द ही बढ़ने वाले थे।'

अपराधियों का बोलबाला

उत्तर पूर्व दिल्ली में लोगों को एक अन्य डर सता रहा है। हिंसा के शिकार और चांदबाग मुख्य सड़क पर एक रेस्तरां चलाने वाले सैफुद्दीन अली ने कहा, 'दिल्ली के इस भाग में विभिन्न गैंगों द्वारा अपने इलाके में आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। तस्करी और जबरन वसूली के अलावा छोटे कारोबारियों को उधारी देकर ब्याज वसूलना उनकी कमाई का मुख्य जरिया है।' अली को अपनी छोटी-सी खानेपीने की दुकान में आठ प्रकार के बर्गर बेचने पर गर्व था। उन्होंने कहा, 'बैंकों ने मुझे ऋण देने से इनकार कर दिया और स्थानीय वित्तीय कंपनियों ने कहा कि उन्हें भरोसा नहीं है कि मेरे जैसा छोटा कारोबार कब तक चलेगा। इसलिए कुर्सियां और दुकान के साजो-सामान खरीदने के लिए मेरे पास सूदखोरों के पास जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।' तमाम लोगों ने पुष्टि की है कि कई कारोबारियों को एक महीने के भीतर ऋण चुकाने का नोटिस मिला है। दंगा शुरू होने के बाद से ही भजनपुरा और चांदबाग सुर्खियों में रहे हैं। छह लेन वाली सड़क से विभाजित इस क्षेत्र में एक ओर हिंदू बहुल आबादी है तो दूसरी ओर मुस्लिम बहुल। सड़क किनारे हिंसा के वीडियो वायरल हो चुके हैं जिसमें भजनपुरा की ओर इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल पंप में लगाई गई आग भी शामिल है।

पेट्रोलियम खुदरा उद्योग के एक संगठन के अनुसार, कंपनी के स्वामित्व और डीलर द्वारा संचालित इस पेट्रोल पंप को आगजनी के कारण करीब 1 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उस पेट्रोल पंप के सामने खड़े 90 वर्ष के अवतार सिंह ने कहा, 'मेरे जीवन में ऐसी एकमात्र घटना 1984 में हुई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, दुकानों में आगजनी की जा रही थी और देखिये, लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें नहीं लगता कि पेट्रोल पंप में आगजनी से एक बड़ी आपदा हो सकती है।'

उस पेट्रोल पंप से कुछ ही सौ मीटर दूर वजीराबाद में एक रिलायंस फ्रेश स्टोर में पिछले मंगलवार को कर्मचारी और खरीदार दो दंगाई समूहों के बीच फंस गए। स्टोर के भीतर शरण लेने वाले राहगीरों सहित करीब 25 लोग लगभग 10 घंटे तक छिपे रहे। दो उन्मादी गुटों- एक भजनपुरा की तरफ से और दूसरा चांदबाग की ओर से- ने रिलायंस फ्रेश स्टोर के सामने वाली सड़क को दो दिनों के लिए युद्धक्षेत्र में बदल दिया। स्टोर के सामने खड़ी आठ बाइक जला दी गईं। इस आउटलेट में रोजाना लगभग 4 लाख रुपये का कारोबार होता था।

चांदबाग की ओर मोटरसाइकिल के कई शोरूम पूरी तरह अथवा आंशिक तौर पर जला गए थे। पुरानी मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की बिक्री करने वाली क्रेडरटू बाइक्स के कर्मचारी रवीश कुमार ने कहा, 'इस आगजनी से एक बाइक को करीब 60 बाइकों का नुकसान हुआ। पास के ही सुजूकी बाइक शोरूम को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और इस क्षेत्र में कम से कम तीन महीने तक कोई कारोबार नहीं होगा।' उन्होंने कहा कि यह शोरूम हर महीने लगभग 60 लाख रुपये का कारोबार करता है। एक फल विक्रेता मोहम्मद रियाज ने कहा, 'मैं फलों की बिक्री से रोजाना 500 से 600 रुपये कमा लेता था। लेकिन पिछले पांच दिनों से कारोबार बंद है और मेरा 15,000 रुपये का सामान बरबाद हो गया। इस बाजार के अधिकांश विक्रेताओं की स्थिति भी मेरे जैसे ही है। कुछ लोगों को तो लाखों का नुकसान हुआ है।'

चांद बाग इलाके में दवा की महज एक दुकान सिद्दीकी मेडिकोज खुली थी। वहां आवश्यक दवाओं और प्राथमिक चिकित्सा सामग्रियों की तेजी से बिक्री हो रही थी। इस दवा दुकान के मालिक फैजल इस्लाम ने केवल इतना कहा, 'राजनेताओं को फायदा हुआ और हमारे जैसे आम लोगों को नुकसान। मैंने पुलिस के कहने के बाद ही आज दुकान खोली है।'

दिन भर साफ-सफाई

इस क्षेत्र में साफ-सफाई के एकमात्र कारोबार में तेजी दिख रही है। लोग जले हुए वाहनों, पिघले हुए लोहे और पत्थरों के मलबे से जितना संभव हो उतना बचाने के लिए उत्सुक हैं। अधिकतर निवासियों ने शिकायत की कि हिंसा खत्म होने के तीन दिन बाद भी नगर निगम के सफाई कर्मचारी इलाके में नहीं पहुंचे हैं। जबकि आसपास सुलगते हुए मलबे के कारण कई लोग झुलस चुके हैं। बारहवीं कक्षा के छात्र मनोज यादव ने कहा, 'इस क्षेत्र में छोटे प्लास्टिक कंटेनर बनाने वाली कई इकाइयां थीं। आग ने रसायनों को चारों ओर फैला दिया होगा। वहां जबरदस्त गंध आ रही है। यहां तक कि मामूली खरोंच या घाव भी तेजी से फैल रहा है और उसमें काफी जलन महसूस हो रहा है। हम काफी डरे हुए हैं।' अन्य निवासियों ने बताया कि अपने जले हुए मकानों की साफ-सफाई के लिए उन्होंने बाहर से लोगों की मदद ली है।

सोमवार को संसद में गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग करते विपक्षी दल

संसद में दिल्ली हिंसा पर भारी हंगामा

अर्चिस मोहन

बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान सोमवार को संसद के दोनों सदनों में दिल्ली में हुई हिंसा का मुद्दा गूंजा जहां विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा किया। लोकसभा में विपक्षी दलों ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के सांसदों के बीच धक्का-मुक्की हुई। राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों ने दिल्ली हिंसा को लेकर चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया और मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह सदन में बयान दें। संसद में सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्षी दलों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया था।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वर्तमान सदस्य जदयू के वैद्यनाथ प्रसाद महतो के पिछले दिनों हुए निधन के कारण दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब हंगामे की वजह से तीसरी बार 4.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिन में करीब 2 बजे विपक्षी दलों विशेषतौर पर कांग्रेस के कुछ सदस्य काले रंग का एक बैनर ले कर सदन के आसन के करीब आ गए जिस पर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई थी।

जब कांग्रेस के गौरव गोगोई और रवनीत सिंह बिट्टू काले रंग का बैनर लेकर सत्ता पक्ष की सीटों की तरफ बढ़ रहे थे उस वक्त भाजपा के संजय जायसवाल प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, पर चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। जायसवाल को इस तरह से बाधित किए जाने का भाजपा सदस्यों ने विरोध किया।

भाजपा के निशिकांत दुबे और रमेश बिधूड़ी सहित कुछ सदस्यों को कांग्रेस सदस्यों से वहां से जाने को कहते हुए देखा गया। कुछ कांग्रेस सदस्यों को कागज के पन्ने फाड़कर हवा में लहराते हुए देखा गया। भाजपा के कई सदस्य कांग्रेस सदस्यों की तरफ तेजी से आते दिखे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का-मुक्की शुरू होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए टाल दी।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और स्मृति इरानी को आपस में उलझे विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच बचाव करते देखा गया।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी सदन में इस हंगामे के दौरान मौजूद थे। इरानी ने बाद में आरोप लगाया कि लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने भाजपा की महिला सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से भी शिकायत की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अराजक तत्व संसद की कार्यवाही को पिछले कुछ सत्र से बाधित कर रहे हैं और वह उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती हैं।

पीठासीन अध्यक्ष रमादेवी ने तीन बजे सदन की बैठक एक घंटे के लिए स्थगित कर दी और उन्होंने कांग्रेस सदस्यों से नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने बहुत गलत किया है। हालांकि इसके बाद भी हंगामा जारी रही। भाजपा के सदस्य भी 'महात्मा गांधी अमर रहें, नकली गांधी जेल में रहें' का नारा लगा रहे थे। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने शाह के इस्तीफे से जुड़े बैनर अध्यक्ष के आसन पर रख दिए लेकिन उसे तुरंत हटा दिया गया। हंगामे के बीच लोकसभा में सरकार की ओर से गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 और खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 पेश किए गए। इसके अलावा अध्यक्ष ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 पर चर्चा शुरू कराने का निर्देश दिया।

राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने बैठक शुरू होने पर सूचीबद्ध दस्तावेज सदन पटल पर प्रस्तुत कराने के बाद बताया कि उन्हें विभिन्न दलों के सदस्यों की ओर से दिल्ली और देश के अन्य इलाकों में कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर चर्चा कराने की मांग कराने संबंधी नोटिस मिले हैं। उन्होंने कहा कि यद्यपि यह विषय महत्त्वपूर्ण है इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन दिल्ली में अब सामान्य हालात बहाल हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपने स्थान पर खड़े होकर इसका विरोध करते हुए इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की।

विदेश यात्रा बुकिंग में भारी कमी

पृष्ठ 1 का शेष

ऑनलाइन ट्रैवल फर्म एक्सपीडिया ने कहा कि वह दुनिया भर में 3,000 कर्मचारियों की छंटनी कर रही है, जिसकी शुरुआत सिंगापुर और हॉन्ग कॉन्ग से की जा रही है। एमिरेट्स और सिंगापुर एयरलाइंस को भी लागत में कमी के उपाय करने पड़ रहे हैं। सिंगापुर एयरलाइंस मुख्य कार्याधिकारियों और वरिष्ठ प्रबंधन सहित अपने कर्मचारियों के वेतन में 5 से 15 फीसदी की कटौती कर रही है। एमिरेट्स ने बिना वेतन स्वैच्छिक अवकाश की पेशकश की है।एक ट्रैवल कंपनी के प्रमुख ने बताया, 'अंतिम समय में बुकिंग रद्द नहीं हो रहे हैं लेकिन नई बुकिंग टाली जा रही है। अप्रैल-जून के दौरान कारोबार को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता।' सैर-सपाटे के लिए इटली भारतीयों का पसंदीदा गंतव्य है। आम तौर पर समूह यात्रा लंदन से शुरू होती है और रोम में खत्म होती है लेकिन कोरोना की वजह से ट्रैवल फर्मों को अपनी योजना पर नए सिरे से काम करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 'हम अपने आपूर्तिकर्ताओं से बात कर रहे हैं और इस पर विचार कर रहे हैं कि यात्रा को स्विटजरलैंड में खत्म किया जा सकता है या इटली की जगह कोई और देश को इसमें शामिल किया जा सकता है।' यात्रा डॉट कॉम की सह-संस्थापक शबीना चोपड़ा ने कहा, 'कोराना के प्रसार की वजह से भारत सरकार ने अपने नागरिकों को जरूरी नहीं होने पर इटली की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। इटली और यूरोपीय देशों में यात्रा के मौसम में काफी संख्या में लोग सैर-सपाटे के लिए जाते हैं। ऐसे में गर्मियों के दौरान बुकिंग में 12 से 15 फीसदी की कमी आ सकती है।'मेकमाईट्रिप के प्रवक्ता ने कहा, 'कोरोना की वजह से विदेशी यात्रा की बुकिंग में निश्चित तौर पर कमी आई है। कुल विदेशी यात्रा कारोबार में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की हिस्सेदारी करीब 20 फीसदी है। ऐसे में कारोबार पर व्यापक असर पड़ने की आशंका है। हालांकि घरेलू यात्रा के लिए बुकिंग में ज्यादा कमी नहीं आई है। कारोबार के लिहाज से हम घरेलू यात्रा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।'

अमेरिका में वायरस से दूसरी मौत

अमेरिका के वॉशिंगटन में स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को कोरोनावायरस से एक और व्यक्ति के मौत की पुष्टि कर दी। यह अमेरिका में इस वायरस से मौत का दूसरा मामला है। वॉशिंगटन में संक्रमित लोगों की तादाद 75 हो चुकी है। ईरान में रविवार को मरने वालों की तादाद 54 हो गई जो चीन के बाहर वायरस के संक्रमण से मरने वालों की सबसे अधिक तादाद है। वहीं ईरान में 978 लोग संक्रमित हो चुके हैं। फ्रांस में भी कोरोनावायरस से मौत का तीसरा मामला सामने आ चुका है। आर्मेनिया, चेक रिपब्लिक, आइसलैंड, इंडोनेशिया में संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि हुई है जबकि गई। चीन से बाहर कोरोवायरस का प्रकोप 66 देशों में देखा जा रहा है। इन देशों में संक्रमण के 8,800 से अधिक मामले की पुष्टि हुई है और 130 लोगों की मौत हो चुकी है। वैश्विक स्तर पर इस बीमारी में 3,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोनावायरस महामारी का तेजी से प्रसार हो रहा है और वैश्विक स्तर पर वायरस संक्रमण के करीब 89,000 मामले की पुष्टि हुई। *एजेंसियां*